।। श्री हरिः ।।

नमामि देवी नर्मदे

अमृत दर्शन

RNI No. MPHIN /2004 /13927

वर्ष - 22 अंक - 189

नर्मदापुरम

रविवार, 26 अप्रैल 2026

● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 1 रुपया

Website : www.amritdarshan.com

नर्मदापुरम का प्रथम हिन्दी दैनिक

खास बात

जो अपने समय का सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं, वे ही समय की कमी की सबसे अधिक शिकायत करते हैं।

-ब्रूयर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं कु. खुशी राय और कु. चांदनी विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री निवास में सम्मानित कर बधाई दी।

मप्र में भीषण गर्मी से बच्चों को राहत

इंदौर-ग्वालियर के स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी, कलेक्टरों ने जारी किए आदेश

इंदौर/ग्वालियर ■ निसं

मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित कर दिया गया है।

30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल: कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल 2026 तक छुट्टी रहेगी। यह निर्णय पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुई अचानक वृद्धि और दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं (लू) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस भीषण गर्मी में छोटे बच्चों का स्कूल जाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

1 मई से शुरू होंगी आधिकारिक गर्मी की छुट्टियां: शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहे हैं। कलेक्टर के इस नए आदेश के बाद अब इंदौर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए छुट्टियां अभी से शुरू हो गई हैं। यानी 30 अप्रैल तक कलेक्टर के आदेशानुसार अवकाश रहेगा और उसके ठीक अगले दिन यानी 1 मई से नियमित गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी।

9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को राहत नहीं: कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पूर्ववत प्रातः 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जायेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बड़े विद्यार्थियों के लिए फिलहाल समय में बदलाव रहेगा लेकिन अवकाश नहीं होगा। इसके अलावा, शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित परीक्षा आदि आवश्यक कार्यक्रम यथावत समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगे।

ग्वालियर जिले में भी अवकाश के आदेश जारी

ग्वालियर जिले में भी अत्यधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए छात्र-छात्राओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं का 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सेंट्रल स्कूल एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों पर लागू होगा।

संक्षिप्त समाचार

बदरीनाथ धाम में बदला मौसम, ऊंची चोटियों पर बारिश-बर्फबारी

चमोली। बीते कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदला। बदरीनाथ धाम में बारिश-बर्फबारी से मौसम में ठंडक आ गई। मौसम विभाग की ओर से आज कई जिलों में बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी जारी की गई थी। विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 4400 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। देर शाम बदरीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।

आज से बिना-हेलमेट पकड़े गए तो होगी कार्रवाई:लाइसेंस तक होगा सस्पेंड

भोपाल। मप्र में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने को लेकर एक बार फिर सख्ती की जाएगी। पीएचक्यू ने 26 अप्रैल से 10 मई तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट चेकिंग के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तों की निगरानी में और प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में चलाया जाएगा। एडीजी पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय विवेक शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी और हेलमेट का उपयोग न करना है।

मुख्यमंत्री ने सुशासन भवन में बुलाई अहम बैठक

बड़े अधिकारी मौजूद, किसान हितैषी योजनाओं पर कर रहे चर्चा

भोपाल ■ विप्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में सीनियर अफसरों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों को दी जाने वाली सौगातों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें अधिकारियों को आज हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए जाएंगे।

आगामी योजनाओं पर किया जा रहा मंथन: मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष को लेकर आज का दिन सुशासन भवन में नीतिगत फैसलों के लिए आरक्षित रखा है। बैठक में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, राजस्व, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग समेत सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। अलग-अलग सेक्टर में किसानों के हित में किए जा सकने वाले कार्यों और आगामी योजनाओं पर मंथन जारी है।

गेहूं खरीदी लक्ष्य में बढ़ोतरी का ऐलान: इससे पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए केंद्र सरकार से खरीदी सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। 22 लाख मीट्रिक टन की यह बढ़ोतरी किसानों की मेहनत का सम्मान है और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन, स्लॉट बुकिंग 9 मई तक

- गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह से खोली जा चुकी है।
- गेहूं खरीदी अब सप्ताह में 6 दिन होगी। शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा।
- खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी लगातार जारी रहेगी। 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को अब 9 मई तक बढ़ा दिया गया है।
- अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।
- उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी।
- किसानों को मात्र पांच रुपए में कृषि पंप का कनेक्शन दिया जा रहा है।
- हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बदले दिन में ही सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले।
- प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नई 1752 दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन का दूध संकलन 10 लाख किलोग्राम से अधिक पहुंच गया है और दुग्ध उत्पादक किसानों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।
- किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपए बढ़कर मिल रहा है।
- इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है।

बंगाल चुनाव: रैली में राजनाथ बोले- परिवर्तन होना तय

राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में जनसभा को संबोधित किया

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में जनसभा को संबोधित किया है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हुगली में जनसंवाद किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विश्वास जताया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन न केवल संभव है, बल्कि निश्चित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले चरण में लगभग 93 फीसदी मतदान से स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो रही है। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि भाजपा या एनडीए सरकार ही इसकी गारंटी दे सकती है।

वहीं हुगली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उन पर कई मामले दर्ज किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर नहीं। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी भाजपा से सीधे नहीं लड़ती हैं। गांधी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे 55 घंटे पूछताछ की, जबकि ममता बनर्जी से कोई पूछताछ नहीं हुई।

भाजपा का विश्वास और टीएमसी पर हमला: राजनाथ सिंह ने कहा कि 2011 में 84 फीसदी मतदान पर वाम सरकार हटी थी, इस बार 93 फीसदी मतदान टीएमसी सरकार के जाने का संकेत है। उन्होंने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को निराशाजनक बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार तथा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया।

गुंडे जेल में होंगे या 'ऊपर' होंगे- राजनाथ सिंह

हुगली में एक रोड शो के दौरान बोलते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि बंगाल में अब गुंडे नहीं रहेंगे। अगर वे रहे, तो वे बंगाल की जेलों में होंगे या 'ऊपर होंगे'... हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हम किसानों को उचित मूल्य देंगे, युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे और साथ ही, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे। सभी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।'

अंतर्मना उवाच

अंधों को उपदेश की नहीं, उपचार की आवश्यकता है..!

चार शब्द हैं --

(1) कार्य (2) उपकार

(3) परोपकार (4) सरकार

- ***कार्य*** *- यानि प्रवृत्ति या उद्यम। कार्य करने वाले व्यक्ति को हित-अहित का विशेष बोध नहीं होता, उसे केवल काम करने से मतलब होता है।*
- ***उपकार*** *- यानि विवेकपूर्ण कार्य, होशपूर्वक की गयी प्रवृति, सद्कार्य। इसमें कर्म के परिणाम (एक्शन-रिएक्शन) का बोध होता है।*

परतापुर, जिला- बांसवाड़ा (राजस्थान) खुले आसमान में भरी दोपहर के 12:30 बजे, 42 डिग्री तापमान में, तपस्वी सम्राट, अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागरजी महाराज सामायिक करते हुए। सूरज की तपिश से धरती तप रही है, पर उनकी साधना अडिग है। न छाँव, न आसन, केवल आत्म-लीनता। पसीने की बूंदें भी मानो तप का अभिषेक कर रही हो...

- ***परोपकार*** *- जो व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर, अपने स्वार्थ और लोभ को त्यागकर, दूसरों के हित में कार्य करता है, वही परोपकारी है। जो उपकार करके भूल जाए, वही सच्चा परोपकार है।*
- ***सरकार*** *- धर्म निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वैसे ही सच्चा शासक प्रजा के हित के लिए जीता है। जो शासक प्रजा का शोषण करे, द्वेष और ईर्ष्या रखे - वह कैसा राजा..?*

समझदार इंसान को इन चारों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए -- ***अग्नि, बीमारी, दुश्मन और स्त्री।*** *क्योंकि --*

ये चारों यदि नियंत्रण में न रहें, तो जीवन में बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं..और यदि सही दिशा में हों, तो यही जीवन को संवार भी सकते हैं...!!!

■ अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज

विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां, कई नाम लगभग तय; जल्द हो सकती है घोषणा

भोपाल ■ विप्र

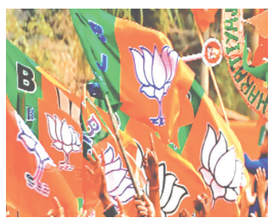

मध्यप्रदेश में विकास प्राधिकरणों और निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई नामों पर सहमति बन चुकी है और सरकार जल्द ही सूची जारी कर सकती है। मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित विकास प्राधिकरणों की नियुक्तियों को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। सरकार और संगठन स्तर पर नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और सूत्रों का कहना है कि सूची कभी भी जारी की जा सकती है। कई शहरों के लिए नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं, जबकि भोपाल और इंदौर जैसे बड़े प्राधिकरणों को लेकर अभी चर्चा जारी है। जानकारी के अनुसार, इस बार केवल अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि कुछ प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी की जा सकती है। इसके जरिए क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इन नामों की चर्चा, अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद : जिन नामों की चर्चा है उनमें देवास विकास प्राधिकरण के लिए बहादुर सिंह मुकाती, जबलपुर के लिए संदीप जैन, ग्वालियर के लिए मधुसूदन भदौरिया, उज्जैन के लिए रवि सोलंकी और रतलाम के लिए मनोज पोरवाल के नाम शामिल बताए जा रहे हैं।

भोपाल-इंदौर प्राधिकरण के नाम को लेकर मंथन

विकास प्राधिकरणों के अलावा निगम-मंडलों में भी नियुक्तियों के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इनमें मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के लिए पूर्व सांसद केपी यादव का नाम चर्चा में है। वहीं अपैक्स बैंक के लिए महेंद्र सिंह यादव और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए संजय नगाइच के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि भोपाल विकास प्राधिकरण और इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। इन दोनों बड़े प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है। माना जा रहा है कि इन नामों पर सहमति बनने के बाद एक साथ पूरी सूची जारी की जा सकती है।

बांग्लादेश पर मंडराया आतंकी हमले का खतरा !

तारिक सरकार ने देश भर में जारी किया अलर्ट, जगह-जगह तलाशी अभियान शुरू

बांग्लादेश ■ एजेंसी

बांग्लादेश पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर वहां की सरकार ने शनिवार को देशभर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर संसद भवन समेत महत्वपूर्ण स्थानों पर संभावित आतंकवादी हमलों की आशंका जताई गई है। इस अलर्ट के बाद देशभर में तलाशी अभियान चलाये गए। पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि भी की है।

इन जगहों पर मंडराया हमले का खतरा: बांग्ला दैनिक प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस मुख्यालय के पत्र में संसद परिसर, पूजा स्थल, मनोरंजन सुविधाएं, सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमलों की चेतावनी दी गई है। हथियार भंडार (आर्मरी) को भी संभावित निशाना बनाये जाने की बात सामने आ रही है।

डेली स्टार और अन्य समाचार पत्रों ने बताया कि यह अलर्ट हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एक ऑपरेटिव इस्तियाक अहमद सामी उर्फ अबू बक्कर की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया है। इस व्यक्ति का दो बर्खास्त सैन्यकर्मियों से संपर्क होने का आरोप है।

ईरान ने किया चौंकाने वाला दावा, उड़ाई अमेरिका की नींद

अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया

नई दिल्ली ■ एजेंसी

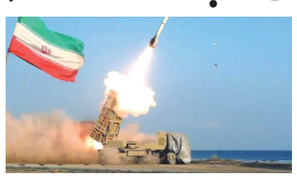

ईरान ने अमेरिका के साथ चल रहे युद्धविराम और दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावनाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने इजरायल और अमेरिका खिलाफ युद्ध में अब तक अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अबतक इस्तेमाल ही नहीं किया है। ईरान का यह दावा तब सामने अया है, जब हाल ही में क्रेमलिन द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया था कि ईरान के पास कुछ ऐसी रहस्यमयी मिसाइलें हैं या हो सकती हैं, जिनकी क्षमता से दुनिया अनजान है। अब ईरान ने यह बयान देकर रूस के उस दावे पर एक तरह से मुहर लगा दी है। इस दावे ने अमेरिका और इजरायल तक को चौंका दिया है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का दावा था कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है।

ईरान के पास अभी भी पर्याप्त उन्नत मिसाइलें बाकी: ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाई-निक ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया गया। जनरल तलाई-निक ने दावा किया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने युद्धविराम (सीजफायर) से ठीक पहले तक इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों के आकाश पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त उन्नत मिसाइलें बाकी हैं, जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकती हैं।

ईरानी मिसाइलों ने इजरायल से लेकर पूरे मिडिल-ईस्ट में मचाई थी तबाही: इजरायल और अमेरिका से युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइलों ने पूरे मिडिल-ईस्ट में भीषण तबाही मचा रखी थीं। इस दौरान 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने अपने जवाबी हमलों में मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। ईरानी अधिकारी इसे अपनी रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा बता रहे हैं। जनरल तलाई-निक ने कहा, 'हमारी मिसाइल क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है।' उन्होंने यह भी बताया कि ईरानी सेना ने संघर्ष के दौरान दुश्मन के आकाश में मजबूत पकड़ बनाए रखी।

नई दिल्ली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वजीराबाद थाना पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार बताया जा रहा है। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि 21 अप्रैल की शाम वजीराबाद क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मोरादाबाद निवासी 49 वर्षीय मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियो ने रुम बुक किया, बहाने से कमरे में बुलाकर की ज्यादती

महिला ने बेटे और उसके दोस्त से होटल में कराया रिसेप्शनिस्ट युवती का रेप

- बाद में महिला सहित दोनो युवको ने पीड़िता को अगवा कर की मारपीट
- आरोपी महिला ने पीड़िता रिसेप्शनिस्ट को दी धमकी- मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना
- सूचना मिलने पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैस कर युवती को किया बरामद

भोपाल ■ निसं

नये शहर के कोलार थाना इलाके में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली युवती के साथ आरोपी महिला द्वारा अपने बेटे और बेटे के दोस्त से उसी होटल में रेप कराये जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी महिला इसी होटल की पूर्व रिसेप्शनिस्ट है। उसने अपने बेटे और बेटे के दोस्त के साथ योजना बनाते हुए पहले दोनो को होटल भेजा और रूम बुक कराया। रुम में जाने के बाद आरोपी बेटे और उसके दोस्त ने रूम में पानी न आने की समस्या बताई। जब पीड़ित युवती कमरे में पानी चेक करने पहुंची तब आरोपियो ने उसे होटल के कमरे में ही बंधक बनाकर बारी-बारी से उसके साथ ज्यादती कर डाली। इसके बाद आरोपी पूर्व रिसेप्शनिस्ट महिला होटल के कमरे में पहुंची और पीड़िता को घटना के संबंध में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं महिला ने दोनों युवकों की मदद से पीड़िता को होटल से जबर्दस्ती अगवा किया तीनो उसे स्टेशन बजरिया इलाके में ले गये और यहाँ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। आरोपी महिला ने पीड़िता से कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। बताया गया है कि आरोपी और पीड़ित महिलाओं का एक होटल मालिक से अफेयर है, जो इन दिनों शहर से बाहर है। पीड़िता और होटल मालिक की फोन पर बातचीत होती है।

रात के समय किया था रुम बुकः थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय युवती ने अपनी शिकायत में बताया की बीकॉम करने के बाद वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे वह होटल में ड्यूटी पर थी। उसी समय आरोपी बिट्टू और एक अन्य युवक के साथ होटल पहुंचा। होटल में ठहरने का कहते हुए आरोपियों ने होटल में कमरा दिखाने के लिए कहा। पीड़िता कमरा दिखाने उनके साथ गई। थोड़ी देर बाद आरोपियों ने पीड़िता से पानी न आने की शिकायत की। पीड़िता जब चैक करने के लिये कमरे में पहुचीं तब दोनो ने उसे जमकर मारपीट की।

मोबाइल लोकेशन ट्रैस कर पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया

इधर होटल में हुई घटना से घबराये होटल स्टॉफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की तलाश के लिये उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उसे स्टेशन बजरिया इलाके से बरामद किया। पुलिस ने बताया की आरोपियों की धमकी और डर से पीड़िता पहले कुछ बताने को तैयार नहीं हुई। थाने लाकर उसकी काउंस्लिंग कराई गई जिसक बाद उसने आरोपिया की सारी करतूत पुलिस को बताई। शनिवार अलसुबह पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियो के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने, अपहरण कर मारपीट करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी महिला विनिता को पकड़ लिया है, जबकि पुलिस कार्यवाही की भनक लगते ही दोनो युवक फरार हो गये। थाना पुलिस का कहना है की पुलिस की दो टीमें आरोपियो की धरपकड़ के प्रयास में जुटी हैं। वहीं विनिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बादमें आई महिला ने धमकी दी, अगवा कर पीटाः थोड़ी देर बाद कमरे में इसी होटल की पूर्व रिसेप्शनिस्ट विनिता आ गई उसने पीड़िता से बात करते हुए युवक को बेटा जबकि बिट्टू को बेटे का दोस्त बताया। साथ ही उसने धमकी दी की वह आज के बाद उसके बॉयफ्रेंड (होटल मालिक) से दूर रहे। इसके बाद तीनो उसे दो पहिया वाहन से जबर्दस्ती अपने साथ बजरिया इलाके में ले गये और वहाँ बंधक बना लिया, आरोपी बिट्टू ने उसके साथ रेप किया और उसके दोस्त ने उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की।

संक्षिप्त समाचार

भोपाल कोर्ट में आम सभा के दौरान वकीलों के बीच हुआ विवाद

भोपाल। इन दिनो जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर)। राजधानी की जिला अदालत में भी सरगर्मी जारी है। इसी बीच आयोजित आम सभा में वकीलो के बीच कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ और नौबत झूमाझटकी तक पहुचं गई। एक पक्ष का आरोप है, कि कार्यकारिणी ने पहले बहुमत से 19 वोटों के साथ जगमोहन शर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी चुना था, लेकिन बाद में अचानक अध्यक्ष की सहमति से इंद्रजीत राजपूत को मुख्य चुनाव अधिकारी बना दिया गया। इस मुद्दे को लेकर पहले गुरुवार शाम को वकीलों ने हंगामा किया था। इसके बाद तय किया गया कि शुक्रवार को मुख्य चुनाव अधिकारी के चयन को लेकर आमसभा बुलाई जाएगी। शुक्रवार को आयोजित आमसभा में भी विवाद हो गया और वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन महीने पहले ही समाप्त हो चुका है। लंबे विरोध के बाद आमसभा को निरस्त कर दिया गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। वहीं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक खरे ने बताया कि आम सभा बुलाई गई थी, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दी गई है और अब चुनाव की तारीख तय की जा रही है, जिसे जल्द घोषित किया जाएगा।

घर के दरवाजे पर बैठकर गांजा बेच रहा 70 साल का महाराज गिरफ्तार

भोपाल। शहर की निशातपुरा थाना पुलिस ने एक ऐसेगांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर के दरवाजे पर बैठकर ही गांजा बेच रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से पॉच हजार कीमत का 235 ग्राम गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी निशातपुरा मनोज पटवा से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि शांति नगर जोड़, विशाल चाट भंडार वाली गली में रहने वाला राजाराम सेन उर्फ महाराज अपने घर के दरवाजे पर बैग में गांजा लेकर उसे बेचने की फिराक में बैठा है। खबर मिलते ही टीम ने घेराबंदी कर आरोपी राजाराम सेन (70) को पकड़ लिया। उसके पास मौजूद काले बैग की तलाशी लेने पर उसमें 235 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का एक्ट का मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया है । आरोपी से गांजे लाने के संबध सहित उसके अन्य साथियो के संबध में पूछताछ की जा रही है।

समय से पहले घर लौटा जिला बदर बदमाश, पुलिस ने धर दबोचा

भोपाल। शहर की शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने एक ऐसे जिलाबदर बदमाश को दबोचा है, जब वह अपने जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले ही अपने घर वापस आ गया था। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में स्थित मदर इंडिया कॉलोनी में रहने वाला आरोपी किशन चंडालिया उर्फ चोटी पिता राजेश उर्फ बबलू (24) आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह मदर इंडिया कॉलोनी में रंगदारी दिखाकर आतंक फैलाता है। उसका रिकार्ड देखते हुए उसे पुलिस कमिश्नर ने दो महीने पहले ही 16 फरवरी को एक साल के लिए जिलाबदर किया था। पुलिस को सूचना मिली की किशन चंडालिया उर्फ चोटी मदर इंडिया कॉलोनी में रहने वाली दादी रामकली चंडालिया के यहॉ आया हुआ था।

17488 स्कूलों में हो रही पानी बिना पढ़ाई

मप्र के हजारों सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नदारद

भोपाल ■ निसं

मप्र में तापमान का पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। गर्मी के कारण लोगों के कंठ सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मप्र के सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन इसी से किया जा सकता है कि यहां के 17488 स्कूलों में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आलम यह है कि या तो बच्चे घर से बोतल में पीने का पानी लेकर स्कूल जा रहे हैं, या नगर-गांव के हैंडपंप पर जाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों के शौचालय केवल शोभा की वस्तु बने हुए हैं।

सरकारी स्कूलों की प्यास बुझाने का दावा करने वाला जल जीवन मिशन नाकाफी रहा है। जहां कागजों पर योजना पूर्ण दिखाई जा रही है, वहां या तो ढांचे जर्जर हैं या फिर नलों से टोटियां गायब हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 93419 सरकारी स्कूलों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य था। प्रशासनिक सुस्ती का आलम यह है कि अब तक केवल 75931 स्कूलों पाई है जबकि 17488 स्कूल आज भी भी इस बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। शौचालयों में पानी की हालत भी खराब है। प्रदेश में मात्र 63066 स्कूलों के शौचालय में ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है। वहीं, हाथ धोने की व्यवस्था 82245 स्कूलों में ही उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में शामिल प्रदेश के 52 में से केवल 13 जिलों ने ही अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। टॉप-5 जिलों में निवाड़ी (506), भोपाल (637), बुरहानपुर (640), हरदा (692) और आगर (753) शामिल हैं। इसके उलट 39 जिले अब भी पीछे हैं।

कई जिलों की स्थिति चिंताजनक

जल जीवन मिशन की विफलता का सबसे बड़ा चेहरा राजगढ़ जिला बनकर उभरा है। 1976 स्कूलों के लक्ष्य के विरुद्ध 1089 स्कूलों में काम हो सका है। जिले के करीब 45 फीसदी यानी 887 स्कूलों में नल से जल पहुंचाना शेष है। भिंड में 1888 के लक्ष्य के 831 स्कूल अब भी अधूरे हैं। छतरपुर की स्थिति भी चिंताजनक है। 2118 स्कूलों का लक्ष्य था। 882 स्कूलों में में मुकाबले काम शुरू नहीं हो पाया। मुरैना जिले में 1272 स्कूलों पानी पहुंच सका है। 784 स्कूलों तक जलापूर्ति बकाया है। बड़वानी के आंकड़े भी भयावह हैं। यहां 3042 स्कूलों का लक्ष्य था, लेकिन सुस्ती ऐसी है कि 1133 स्कूलों में योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इन पांचों जिलों के संयुक्त आंकड़े को देखें तो करीब 4517 स्कूलों में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो सका है। भोपाल संभाग के सीहोर, रायसेन, विदिशा जिले को देखें तो सीहोर की प्रगति अच्छी है। जिले के 1469 स्कूलों के लक्ष्य के मुकाबले 1467 में कार्य पूर्ण है। महज 2 स्कूल शेष बचे हैं। विदिशा जिले की स्थिति दयनीय है। यहां 1998 स्कूलों का लक्ष्य होने के बावजूद 748 स्कूलों में काम शुरू नहीं हो सका है।

ढांचा तैयार, टोंटियां गायबः जन जीवन मिशन के तहत स्कूलों में पानी पहुंचाने के दावों की हकीकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रायसेन के सांची ब्लॉक के भैंसाया के शासकीय प्राथमिक शाला में पानी के लिए बनाए गए ढांचे तो दिखे, लेकिन उनमें लगी टोंटियां गायब हैं। यहां सिर्फ पुरानी व्यवस्था के अवशेष बचे हैं। न तो स्कूल की छत पर टंकी है और न ही परिसर में। बच्चों की उम्मीदों का एकमात्र सहारा हैंडपंप भी जर्जर और खराब पड़ा है। विदिशा के तोपपुरा प्राथमिक शाला में मिशन अब तक नहीं पहुंच सका। योजना के नाम पर बना ढांचा अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पेयजल के लिए छात्र हैंडपंप पर निर्भर हैं। शौचालय में पानी का नामोनिशान नहीं है। यही बदहाली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला जतरापुरा में भी साफ दिखाई देती है। गुना के मातापुरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में भी नल से जल का सपना दिखावटी है। यहां बना ढांचा जर्जर है और टॉटियों का कोई अता-पता नहीं। पानी के अभाव में शौचालय बंद रहते हैं। हैंडपंप ही सहारा है। गोपालपुरा शासकीय प्राथमिक स्कूल में हैंडपंप खराब है। वहां शहर की टंकी से सप्लाई होती है, पर बिजली न होने पर पानी नहीं आता। आंगनबाड़ी में चोरी के डर से टंकी शौचालय के अंदर कैद मिली। यहां वॉश बेसिन में टोंटी होने के बावजूद पानी नदारद है।

लव जिहाद की शिकार इंजीनियरिंग छात्रा के समर्थन में उतरा मुस्लिम संगठन

पहचान छिपाकर छात्रा से की ज्यादती, गर्भवती होने पर किया शादी से इंकार

सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर संगठन ने दी सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी जाएगा।

भोपाल ■ निसं

राजधानी के महिला थाना में 5 मार्च को दर्ज इंजीनियरिंग छात्रा के साथ कथित धोखाधड़ी, ज्यादती और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में अब तक आरोपियो की गिरफ्तारी न होने पर पहली बार एक मुस्लिम संगठन ने पीड़िता के समर्थन में आते हुए उसे न्याय दिलाने के लिये आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रकरण को शर्मनाक बताने के साथ ही आरोपियो की सात दिन में गिरफ्तारी की मांग करते हुए सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी दी है।

पहचान छिपाकर बढ़ाई थी नजदीकियां, फिर की ज्यादतीः आईईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने महिला थाना में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है, कि उसकी साल 2023 में पहचान एक युवक से हुई थी। उसने अपना खुद का नाम 'आशीष पांडे' बताया। दोस्ती के बाद नजदीकियां बढ़ाते हुए आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और जल्द शादी करने का वादा कर छात्रा का कई बार दैहिक शोषण किया। आरोप यह भी है कि आरोपी ने रिश्ते के दौरान उससे ऑनलाइन और नकद पैसे भी लिए। बाद में जब उसे जानकारी लगी की उसका असली नाम आसिफ रजा है। जब उसने शादी की बात की, तो आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया।

गर्भवती होने पर दोस्तो के साथ घर जाकर धमकाया

पीड़िता का आरोप है कि जनवरी 2026 में जब आरोपी को गर्भवती होने की बात बताई तब उसने अपने दो साथियों के साथ उसके घर आकर शादी करने से इनकार करते हुए उसे मार डालने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। छात्रा के मना करने पर उसे लगातार धमकियां मिलती रहीं।

गंभीर धाराओ में मामला दर्जः महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 60, 351(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(डु) और 5 भी लगाई गई हैं, जो जबरन धर्म परिवर्तन और उससे जुड़े कृत्यों से संबंधित हैं।

एआई की निगरानी में होगी एमपीपीएससी परीक्षाएं

आज होने वाली राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 से एआई आधारित कमांड सेंटर से लाइव निगरानी

भोपाल ■ निसं

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। यह नई व्यवस्था राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 से लागू की जा रही है, जो रविवार को आयोजित होगी।

आयोग के चेयरमैन राजेश लाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से अधिकारियों को 54 जिलों के 365 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ नजर रखने की सुविधा मिलेगी। परीक्षा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो कमांड सेंटर से सीधे संबंधित केंद्राध्यक्ष को निर्देश दिए जाएंगे।

पहली बार ऐसा निगरानी सिस्टम लागूः परीक्षा में पहली बार त्रिस्तरीय जांच प्रणाली लागू की गई है। यह नकल रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) से तलाशी शामिल है। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आंखों की पुतलियों (आइरिस) का मिलान भी किया जाएगा, जिससे फर्जी अभ्यर्थियों की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक कक्ष भी कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक मिलान नहीं होता है तो इसकी जानकारी तुरंत कमांड सेंटर को दी जाएगी और आगे की कार्रवाई वहीं से तय होगी।

30 सेकंड से ज्यादा ठहरने पर अलर्टः पूरी परीक्षा प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। प्रत्येक कक्ष में अधिकतम 24 अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा और उनके साथ दो पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। यदि कोई पर्यवेक्षक किसी अभ्यर्थी के पास 30 सेकंड से अधिक समय तक रुकता है, तो कमांड सेंटर से तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा और संबंधित पर्यवेक्षक को स्पष्टीकरण देना होगा।

प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर में 121 महाकुण्डीय यज्ञ हेतु भूमि पूजन

भोपाल। शहर के प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर में विगत 32 वर्षों से शनि जयंती के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले 121 महाकुण्डीय यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को कोटरा नेहरू नगर में विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन पूज्य गुरुजनों के सान्निध्य में भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मोनू सक्सेना एवं पार्षद वीनू मोनू सक्सेना द्वारा क्षेत्रीय रहवासियों के साथ संपन्न किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंखनाद के बीच भूमि पूजन कर महायज्ञ की तैयारियों का शुभारंभ किया गया नवग्रह शनि मंदिर में पिछले 32 वर्षों से निरंतर शनि जयंती पर 121 महाकुण्डीय यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है। यह यज्ञ प्रदेश के सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है।

पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार साई इंफ्राटेक को किया ब्लैकलिस्ट

घटिया कार्य के चलते सहायक यंत्री एवं उप यंत्री को नोटिस

भोपाल ■ निसं

लोक निर्माण विभाग ने घटिया निर्माण के चलते ठेकेदार मेसर्स साई इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 कामों की गुणवत्ता सुधारने को कहा है। निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते सहायक यंत्री एवं उप यंत्री को नोटिस जारी किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने हरदा, मंडला, ग्वालियर, इंदौर, सतना, देवास एवं पन्ना जिले में 35 कार्यों का रैंडम आधार पर चयन कर परीक्षण किया। निरीक्षित कार्यों में 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सडक़/पुल), 6 कार्य पीआईयू (भवन), 7 कार्य मप्र सडक विकास निगम तथा 1 कार्य म.प्र. भवन विकास निगम से संबंधित थे।

पन्ना जिले में गुनौरगंज-चंदला मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा ठेकेदार मेसर्स साई इंफ्राटेक को काली सूची में डालने के लिये निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य 31 कार्यों में आंशिक सुधार के निर्देश जारी किए गए। इंदौर जिले में आईडीसी द्वारा इंदौर-उज्जैन (एसएच-59) मार्ग के 6 लेन निर्माण कार्य को संतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार मेसर्स महाकाल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड की प्रशंसा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में दी गई अनुशंसाओं का पालन करते हुए आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएं।

वीआईटी विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं की जान से किया जा रहा खिलवाड़, प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा

300 से ज्यादा छात्र छात्राएं दूषित पानी और खाने की वजह से हुई बीमार

भोपाल ■ निसं

सीहोर स्थित वीआईटी विश्वविद्यालय में लगातार सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं ने एक बार फिर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाल ही में दूषित पानी एवं भोजन के कारण लगभग 300 से अधिक छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, वहीं दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं में टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय में दूषित भोजन के कारण एक छात्रा की मृत्यु हो चुकी है तथा सैकड़ों छात्र-छात्राएं बीमार पड़े थे। उस घटना के बाद ओशित विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें तोडफ़ोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई थीं। लेकिन इतनी गंभीर घटना के बाद भी प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जो अत्यंत चिंताजनक है।

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि एनएसयूआई लंबे समय से वीआईटी विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, लापरवाही और छात्रों की जान से खिलवाड़ जैसे मामलों को लेकर शासन-प्रशासन को लगातार अवगत कराता रहा है। एनएसयूआई द्वारा इस संबंध में मानव अधिकार आयोग को भी विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

VIT यूनिवर्सिटी की लापरवाही।
गंदा खाना खाने से 300 छात्र बीमार

रवि परमार ने बताया कि मानव अधिकार आयोग ने दो सप्ताह में जवाब मांगा था लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक उदासीनता और संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि शिक्षा माफियाओं के दबाव में मामले को जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही वीआईटी विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, दोषियों पर सख्त दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो संगठन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का घेराव करने के लिए बाध्य होगा। एनएसयूआई छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और किसी भी स्थिति में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन अब 30 अप्रैल को

3 से 8 हजार पाने वाले अस्थायी, ठेका श्रमिक कर्मचारियों का आंदोलन भोपाल में होगा

भोपाल ■ निसं

भोपाल में अस्थायी, ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रस्तावित सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन अब 28 की बजाय 30 अप्रैल को होगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के चलते आंदोलन की तारीख बदली गई है। कर्मचारी अब नीलम पार्क में प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे। यह आंदोलन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी 12,425 से बढ़ाकर 16,769 रुपए प्रति माह लागू करने और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है।

कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के तय मानकों के बावजूद राज्य के कई विभागों में 3 से 5 हजार रुपए महीने में काम कराया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी ले और इसे बढ़ाकर 26 हजार रुपए प्रति माह किया जाए। अस्थायी, आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखकर आंदोलन की सूचना दे दी है।

बुरहानपुर की महिलाएँ अब पर्यटन की नई ताकत बन रही हैं

'महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना' - एक सशक्तिकरण की सफल मिसाल

खंडवा ■ निसं

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से द फिफ्थ डायमेंशन एकेडमी द्वारा संचालित 'महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना' जिले में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। निर्भया फंड के तहत चल रही इस परियोजना ने स्थानीय महिलाओं को आत्मरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक स्वावलंबन का नया मार्ग दिखाया है।

परियोजना के अंतर्गत लगभग 2000 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस (आत्मरक्षा) की ट्रेनिंग दी गई है, जबकि 400 महिलाओं को हॉस्पिटैलिटी, टूरिस्ट गाइडिंग, होमस्टे मैनेजमेंट, हैंडीक्राफ्ट आदि क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जोड़ा गया है। इन सभी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की अतिरिक्त ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है, जिससे उनके अंदर न केवल आत्मविश्वास बल्कि अपने क्षेत्र, शहर और पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

महिला फेडरेशन का गठन इस परियोजना की सबसे मजबूत कड़ी है। इस फेडरेशन के माध्यम से योजना को सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, ताकि महिलाएँ स्वयं इसे आगे चलाएँ और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलता रहे। फेडरेशन की सक्रिय सदस्याएँ अब पर्यटन सखी के रूप में कार्य कर रही हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं।

पर्यटन सुविधाओं में नई शुरुआत: अब परियोजना के अगले चरण में टूरिस्ट फैसिलिटेटर सेंटर खोला जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से बुरहानपुर आने वाले पर्यटकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी – स्थानीय परिवहन, गाइड, होटल/होमस्टे बुकिंग, स्मारक/स्मारकों की जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि। यह केंद्र पूरी तरह महिला सखियों और महिला फेडरेशन द्वारा संचालित होगा, जो

महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा।

जिला प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर और एसपी सहित समूची टीम ने परियोजना को पूर्ण समर्थन दिया है। सामाजिक ऑडिट के माध्यम से पर्यटन स्थलों की कमियों (अंधेरे वाले इलाके, लाइटिंग, शौचालय आदि) को चिन्हित कर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित समाधान किए गए। पुरातत्व केंद्रों पर नए शौचालय बनवाए गए और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर सराहना: दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में इसी पैटर्न से संचलित करने का सुझाव दिया। डायरेक्टर माधुरी शर्मा का कहना है – 'यह परियोजना सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में नई ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और शहर के प्रति लगाव पैदा कर रही है। हमारी रणनीति स्पष्ट है – पहले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाएँ मजबूत करें, फिर उन्हें सुरक्षित और यादगार अनुभव दें।'

संस्था द्वारा बुरहानपुर के प्रमुख स्मारकों- असीरगढ़ किला, पुरातत्व शिव मंदिर, काला ताज, कुण्डी भंडारा, दरगाह-ए-हकीमी, शनवारा गेट, जामा मंदिर, मोहना संगम, रेणुका मंदिर, राजा जयसिंह की छतरी, आहुखाना आदि एतिहासिक स्थलों की संस्था द्वारा प्रोमोशनल वीडियो फिल्म भी तैयार की गई है, जिससे फिल्म शूटिंग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बुरहानपुर के समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान मिल सकेगी7

संस्था डायरेक्टर माधुरी शर्मा आगे बताती हैं, 'कुछ वर्ष पहले यहां पर्यटक कम आते थे, लेकिन आज महिलाओं की भागीदारी से शहर की तस्वीर बदल रही है। स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और हमारी टीम के सामूहिक प्रयास से बुरहानपुर जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। ' यह परियोजना महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षित पर्यटन और समावेशी विकास का अनुपम उदाहरण बनकर उभरी है। बुरहानपुर अब न केवल ऐतिहासिक स्मारकों के लिए, बल्कि महिला-नेतृत्व वाले पर्यटन के लिए भी जाना जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

खरीदी केंद्रों पर लापरवाही, कलेक्टर ने जारी किए नोटिस

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर चल रही लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने शनिवार को केंद्रों के निरीक्षण किया। इस दौरान इंतजामों में कमी और काम में गड़बड़ी मिलने पर कई समितियों को नोटिस थमा दिए गए हैं। प्रशासन ने तीन दिन के भीतर इन सभी से जवाब मांगा है। कलेक्टर के आदेश पर सिंहपुर, उसरी, मुंगवानी, धमना, नरसिंहपुर, बचई करहैया और कोदसा जैसी सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों, प्रभारियों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा बकौरी के सरस्वती स्वसहायता समूह से भी जवाब-तलब किया गया है। गेहूं की क्वालिटी चेक करने वाली कंपनी आर.बी. एसोसिएट्स के सुपरवाइजर को भी चेतावनी दी गई है कि वे केंद्रों पर जरूरी जांच किट तुरंत मुहैया कराएं। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि राजस्व, खाद्य, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी लगातार केंद्रों का दौरा करें। अगर आगे भी किसी केंद्र पर अनियमितता मिली, तो जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

देवास की झोपड़ी में 7 लाख रुपए के नोट जले

देवास। देवास में शनिवार को 4 झोपड़ियों में आग लग गई। एक व्यापारी के करीब सात लाख रुपए जल गए। मौके से ढाई लाख रुपए के अधजले नोटों की गड्डियां मिलीं। आग से पास के खाटूश्याम मंदिर को भी नुकसान हुआ। हादसा नेवरी फाटा इलाके में शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे चौकी के पीछे हुआ। झोपड़ियों में रहने वालों ने किसी तरह जान बचाई, लेकिन अधिकांश सामान जल गया। सूचना मिलते ही देवास और सोनकच्छ से फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचीं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 2:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। झोपड़ी मालिक बाबूलाल नाथ ने बताया कि वह साबूदाना, निरमा, प्लास्टिक टब आदि अलग-अलग राज्यों में बेचने जाते हैं।

भिंड में दो टीआई समेत सात थानेदारों का ट्रांसफर

असवार पहुंचे सुरेश मिश्रा, परशुराम को एंडोरी से रावतपुरा भेजा

भिंड ■ निसं

भिंड जिले में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक असित यादव द्वारा जारी आदेश में दो निरीक्षकों (टीआई) सहित सात थाना प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार, आलमपुर थाना प्रभारी संजय उपाध्याय को दबोह थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दबोह में पदस्थ राजेश शर्मा को पुलिस लाइन भिंड भेजा गया है। इसी क्रम में असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई को कोतवाली थाना पदस्थ किया गया है।

कमलकांत दुबे को देहात थाना की कमान: रावतपुरा थाना प्रभारी कमलकांत दुबे को देहात थाना की कमान दी गई है। वहीं कोतवाली में पदस्थ सुरेश मिश्रा को स्थानांतरित कर असवार थाना प्रभारी बनाया गया है। देहात थाना में पदस्थ बलराम यादव को झाकरी चौकी भेजा गया है, जबकि झाकरी चौकी प्रभारी विवेक प्रमात को एंडोरी थाना पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा एंडोरी थाना प्रभारी परशुराम अहिरवार को रावतपुरा थाना का प्रभारी बनाया गया है। कोतवाली में पदस्थ सोनेश तोमर को आलमपुर थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी तत्काल अपने नए स्थान पर जॉइनिंग दें। इस व्यापक फेरबदल को जिले में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फर्जी मार्कशीट से 10 साल नौकरी, हॉस्टल अधीक्षक दोषी

खंडवा कोर्ट से 3 साल की सजा; मार्कशीट फाड़ने पर सास को 6 महीने की सजा

खंडवा। फर्जी अंकसूची के आधार पर शासकीय नौकरी हासिल कर करीब एक दशक तक सेवा करने वाले हॉस्टल अधीक्षक को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने आरोपी मोहन सिंह काजले को 3 साल के कठोर कारावास और 27 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। साल 2021 से न्यायालय में लंबित इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अश्विनी भाटे ने पैरवी की। मामले में सहआरोपी उसकी सास भगवती बाई को भी दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

फर्जी मार्कशीट के दम पर मिली नौकरी: अभियोजन के अनुसार, मोहन सिंह काजले ने स्नातक की फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई और उसी के आधार पर खरगोन जिले में शासकीय नौकरी प्राप्त कर ली। वह लगभग 10 सालों तक इस फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करता रहा।

मामले का खुलासा होने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दिसंबर 2020 में आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 201 और 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

खरगोन। आज मानव अधिकार संरक्षण संगठन एचआरडी के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह रावत के द्वारा कार्यालय मानव अधिकार संरक्षण संगठन जिला खरगोन में राहगीरों के लिए शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था की गई मानव अधिकार संरक्षण की टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष मनोज जोशी, नरेंद्र सोलंकी नरेंद्र भटोरे संजय वर्मा आदि उपस्थित रहे।

भोपाल। कुचबंदिया समाज उत्थान कल्याण समितिभोपाल द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में द्वारका नगर स्थित काली मंदिर से रेलवे ग्राउंड एक नंबर प्लेटफार्म के लिए 14 जोड़ों की बारात धूमधाम से निकली। समाज के अध्यक्ष राकेश कुचबंदिया भी उपस्थित थे।

नरसिंहपुर में हाइवा ड्राइवर की करंट से मौत

तिरपाल से रेत ढंकने गाड़ी के ऊपर चढ़ा था, तारों से टकराया

नरसिंहपुर ■ निसं

नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के संसारखेड़ा गांव में शनिवार दोपहर रेत से भरे हाइवा पर तिरपाल डालते समय ड्राइवर बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, रायसेन जिले का रहने वाला 39 साल का वीरेंद्र आदिवासी रेत भरने के बाद हाइवा को तिरपाल (तारपोलिन) से ढंकने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ा था। इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से टकरा गया।

हादसे की खबर मिलते ही डायल 112, एंबुलेंस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं। करंट की वजह से वाहन से धुआं उठने लगा था, जिसे दमकल कर्मियों ने समय रहते बुझा दिया और बड़ा हादसा टल गया।

जांच में जुटी पुलिस: साईंखेड़ा थाना प्रभारी संधीर चौधरी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुई। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह हाइवा किसका है और रेत कहां से लाई जा रही थी।

बस ने बाइक सवारों को कुचला, 3 दोस्तों की मौत

भिंड में 5 किमी तक घसीटी बाइक, सड़क पर चिंगारियां उठती रहीं; एक गंभीर घायल

भिंड ■ निसं

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार को नेशनल हाईवे 552 पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचल दिया। बस बाइक को करीब 5 किलोमीटर तक घसीटते ले गई, जिससे सड़क पर चिंगारियां उठती रहीं। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक है।

वीडियो में दिख रहा है कि बस को रोकने के लिए एक कार सवार ने उसका पीछा किया। कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद बस चालक ने वाहन नहीं रोका। बस बाइक को किशोर सिंह का पुरा से उमरी कस्बे तक घसीटती रही। हालांकि, कुछ दूरी पर जाकर बस रुक गई।।

जैसे ही बस रुकी, उसमें सवार

यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे बस से कूदकर भागने लगे। इसी दौरान बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक और घायल खून से लथपथ सड़क पर पड़े रहे।

शादी में शामिल होने मेहदा जा रहे थे: उमरी पुलिस के मुताबिक, मृतकों में मुरैना निवासी आशुतोष बघेल (21), भिंड के खैरोली निवासी रामकेश बघेल (19) और मुरैना निवासी मोहित बघेल (20) शामिल हैं। वहीं भिंड के मेहदा निवासी अमित बघेल (17) की हालत गंभीर है। सभी शादी में शामिल होने मेहदा जा रहे थे।

बस में अफरा-तफरी मची, चालक मौके से फरार हुआ: घायल युवक को भिंड जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। नाजुक हालत में ग्वालियर रेफर किया गया, पर एंबुलेंस न होने के कारण वह करीब एक घंटे तक अस्पताल में दर्द से तड़पता रहा। यह लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

फरार बस चालक की तलाश जारी: उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत-बचाव कार्य शुरू कराया गया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फरार बस चालक की तलाश जारी है।

वार्ड में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद

शिवपुरी जिला अस्पताल में गार्डों ने की मारपीट: पास दिखाने के बाद अटेंडर को पीटा

शिवपुरी ■ निसं

शिवपुरी जिला अस्पताल में वार्ड में जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो में दो महिला गार्ड सहित चार गार्ड एक अटेंडर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कोलारस के पचावला गांव निवासी सचिन गोस्वामी ने बताया कि उनकी भाभी दो दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार को उन्होंने नियम के अनुसार पास बनवाया और खाना देने वार्ड की ओर जा रहे थे।

सचिन का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड भास्कर राजे ने उन्हें वार्ड में जाने से रोक दिया। पास दिखाने के बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर गार्ड ने अन्य कर्मचारियों को बुला लिया। इनमें एक शाक्य गार्ड और महिला गार्ड सोनम व राजकुमारी शामिल थीं। इसके बाद सभी ने मिलकर सचिन के साथ मारपीट की।

दूसरे अटेंडर के साथ भी हाथापाई का आरोप: पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि इसी दौरान एक अन्य अटेंडर के साथ भी गार्डों ने मारपीट की। वायरल वीडियो में गार्ड एक व्यक्ति को घेरकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और गार्डों के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

अशोकनगर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी पकड़े

फर्जी बैंक खातों से लाखों-करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा

अशोकनगर ■ निसं

अशोकनगर पुलिस ने फर्जी बैंक खाते खोलकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो दूसरे राज्यों से जुड़े सदस्य हैं।

मामले की शुरुआत 7 अप्रैल को हुई, जब तार वाले बालाजी मंदिर क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय रौनक यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके दस्तावेजों का उपयोग

कर बिना जानकारी के बैंक खाते खोले गए।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने करन अहिरवार, सुयाश सिंघई, जितेंद्र पुरी और प्रवल प्रताप सिंह तोमर को गिरफ्तार किया था। इनके मोबाइल की जांच में बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेनदेन सामने आए।

उन्नाव में दबिश, दो अंतर्राज्यीय आरोपी पकड़े: तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दबिश देकर अमित पासी (27) और विजयकांत परिहार (31) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने जियो पेमेंट बैंक खातों की आईडी, पासवर्ड और ओटीपी उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की।

इसी कार्रवाई में ग्राम पडरिया निवासी 19 वर्षीय मनीष अहिरवार को भी गिरफ्तार किया गया। उसने फर्जी खाते खोलकर उनकी जानकारी बेंगलुरु के एक अज्ञात व्यक्ति को देने की बात कबूल की।

करोड़ों के लेनदेन की आशंका, जांच जारी: पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए लाखों से लेकर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन की आशंका है। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक रविप्रताप सिंह चौहान, निरीक्षक नरेश रावत (सायबर सेल) सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।

पिता की हत्या के आरोपी पर 5 हजार का इनाम

इंस्टाग्राम पर दे चुका है धमकी, 6 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

बड़वानी ■ निसं

बड़वानी पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी चंदन बडोले की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। वारदात को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

यह घटना 20 अप्रैल को पिछोड़ी गांव में हुई थी। 35 वर्षीय चंदन बडोले का अपने 58 वर्षीय पिता जगन बडोले से रुपयों को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर चंदन ने सरेराह पिता के सिर में पिस्तौल से गोली मार दी, जिससे जगन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 241/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हत्या के दो दिन बाद, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपने भतीजे के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और धमकी दी। पोस्ट में उसने लिखा कि यदि उसके भाई की पत्नी की शादी हुई, तो शादी करने और करवाने वालों को वह 'भयानक मौत' देगा। उसने यह भी दावा किया कि यह शादी उसके पिता के कारण हो रही है। इस धमकी भरे पोस्ट के बाद से गांव में दहशत का माहौल है।

पुलिस ने तीन दिन पहले आरोपी की मोबाइल लोकेशन बावनगजा की पहाड़ियों में ट्रेस की थी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने वन क्षेत्र में कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका।

अनमोल वचन

आशा कभी आपको छोड़कर नहीं जाती है, आप इसे छोड़ते है।
जॉर्ज वीनवर्ग

मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है।
चाणक्य

सम्पादकीय

एक देश, 2 मतदाता सूची, 2 किस्म के नागरिक

देश में इस समय एसआईआर केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारोंके चुनाव अधिकारों को लेकर देशभर में चर्चा का विषय बनकर सामने आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 22 से अधिक राज्यों में एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चला रखा है। अभी तक जिन राज्यों में एसआईआर हुई है, उन राज्यों में लगभग 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें मतदान योग्य नागरिक नहीं माना है। जिस तरह से अभी तक एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसके अनुसार एसआईआर का काम पूर्ण होने पर लगभग 10 करोड़ मतदाताओं के नाम कटना तय माना जा रहा है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग द्वारा भी नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार की जाती है राज्य स्तर की मतदाता सूची और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में बड़े राज्यों में करोड़ों मतदाताओं का अंतर है। इस बात को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उजागर करते हुए कहा था, राज्य की मतदाता सूची में जो नाम दर्ज हैं, उनके नाम केंद्रीय मतदाता सूची में क्यों नहीं हैं। यही सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार उठाती आ रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरु हो गई है। म.प्र. के राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है, 2027 में होने वाले चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर जो परिसीमन हुआ था। वह मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग मान्य नहीं कर रहा है। जिस तरह की स्थिति देश में चुनावों को लेकर बन रही है, उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोग राज्य की तैयार मतदाता सूची से ही चुनाव कराना चाहती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण राज्य में जगह-जगह मतदाता विरोध में खड़े हो जाएंगे। राज्यों में स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में राज्यों की राजनैतिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिस तरह के हालत अभी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यह कहने में संकोच नहीं है, भारत एक देश है। इसके बाद भी केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची अलग-अलग है। केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम कानून और निर्देश पर राज्यों के चुनाव आयोग काम करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग जिन्हें मतदाता नहीं मान रहा है। राज्य का चुनाव आयोग उन्हें मतदाता मानता है। नागरिकता तय करने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। केंद्रीय गृह मंत्रालय चुप है। अब नागरिकता और मतदाता के मतदान का अधिकार तय करने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है। इसको लेकर जिस तरह की अपरा तफरी सारे देश में मची हुई है, उसमें अब न्यायपालिका भी चर्चाओं में आ गई है। 10 महीने से ज्यादा हो गए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। न्यायपालिका अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराई जा रही है। वह संवैधानिक है या नहीं इसका फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया है। सारी याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इसी बीच राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, एसआईआई भी हो रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह स्थिति पहली बार संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लागू होने पर देखने को मिल रही है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजों को एसआईआर के काम में लगा दिया है। जिससे न्यायपालिका खुद पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। यह स्थिति राजनीतिक प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के लिए आगे चलकर बड़ी चुनौती बन सकती है। जिस तरह से मतदाताओं के अधिकारी पर केंची चलाई जा रही है, संवैधानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी जिनके उपर है वह नागरिकों के जब मौलिक अधिकार खत्म किये जा रहे हों, उस समय वह चुप बैठकर तमाश देखें, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। न्यायपालिका जिस तरह सरकार के दबाव में तारीख पर तारीख, आधे-अधूरे निर्णय देकर अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है, इससे आम जनमानस के बीच न्यायपालिका की साख कमजोर होती जा रही है। कानून का राज तभी तक रहता है जब तक जनता कानून मानती है। कानून पर विश्वास नहीं होगा तो जनता भीड़तंत्र और अराजकता के कानून को मानने लगती है। सरकार और न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरुरत है।

चिंतन-मनन

भावना भी समझें

एक आदमी बस में रोजाना ही यात्रा करता था। वह बस में केले खाता और छिलके को खिड़की से फेंक देता। एक दिन एक भाई ने कहा, भाई! सड़क पर छिलके डालना उचित नहीं है। दूसरे फिसलकर गिर पड़ते हैं। छिलकों को एक ओर डालना चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन की बात है। पूर्व दिन वाले दोनों यात्री एक ही बस में बैठे हुए थे। एक ने केले छीले, खाए और छिलके डाल दिए। सड़क पर नहीं, अन्यत्र कहीं। साथी ने कहा, धन्यवाद! कल जो मैंने कहा, उसे तुमने मान लिया। आज छिलके सड़क पर नहीं फेंके। उसने कहा, सड़क पर तो नहीं फेंके, पर मेरे पास जो दूसरा यात्री बैठा था, उसकी जेब में चुपके से छिलके डाल दिए। सड़क पर उन्हें डालने की नौबत ही नहीं आई। हर आदमी ऐसे ही समस्या को दूसरों की जेब में डालता जाता है और यह मान लेता है कि समस्या का समाधान हो गया। समस्या सुलझती नहीं। एक समस्या सुलझती है, तो दूसरी उलझ जाती है। समस्या के समाधान का सही मार्ग है- भावनाओं पर ध्यान देना। जो भी काम किया जाता है, उसको करने से पूर्व यह सोचना होगा कि मैं यह काम शरीर की सुविधा के लिए कर रहा हूं, पर इससे कहीं मन की समस्या उलझ तो नहीं रही है कहीं भावना की समस्या गहरी तो नहीं होती जा रही है हम तीनों समस्याओं पर एक साथ ध्यान दें। जब तक शरीर की समस्या, मन की समस्या और भावना की समस्या पर समवेत रूप में ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाधान नहीं मिलेगा।

पश्चिमी बंगाल की बंपर वोटिंग रचेगी नया इतिहास

मनोज कुमार अग्रवाल

जब लगभग नब्बे प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि जनता केवल दर्शक नहीं रहना चाहती, जनता जागरूक हो चुकी है बल्कि सत्ता के गठन में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि इस बंपर वोटिंग के मायने क्या है और क्यों तृणमूल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं।

देश के अब तक के संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी राज्य का चुनाव मतदान है जिसमें इतना बंपर तादाद में मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर नया रिकार्ड बनाने की पहल की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की जनता ने इस बार बंपर मतदान किया है, जो राज्य की राजनीतिक चेतना, सामाजिक सक्रियता और लोकतांत्रिक भागीदारी का जीवंत उदाहरण है। पहले चरण में 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक चेतना, सामाजिक सक्रियता और लोकतांत्रिक भागीदारी का जीवंत उदाहरण है। जब लगभग नब्बे प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि जनता केवल दर्शक नहीं रहना चाहती, जनता जागरूक हो चुकी है बल्कि सत्ता के गठन में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि इस बंपर वोटिंग के मायने क्या है और क्यों तृणमूल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इन सबके बीच सबसे पहले, इतने बड़े पैमाने पर मतदान को लोकतंत्र की मजबूती के रूप में देखा जाना चाहिए। अक्सर यह धारणा रही है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहता है और ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक, लेकिन इस बार जिस तरह से हर वर्ग महिला, युवा, बुजुर्ग ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। यह दर्शाता है कि लोगों में अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। खासकर महिलाओं को बड़ी भागीदारी यह संकेत देती है कि वे अब केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक निर्णयों में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव पूर्व में बंगाल में हुए चुनावों के मुकाबले हिंसा कम हुआ है। बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि यह भी सच है कि मुर्शिदाबाद के नौदा और बीरभूम के खैराशोल जैसे क्षेत्रों में हिंसा और और ईवीएम ईवीएम से से जुड़ी शिकायतों कायतों ने ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। झड़पें, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं यह बताती हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब भी कई जगहों पर असहिष्णुता में बदल जाती है। चुनाव आयोग और प्रशासन की जिश्वमेदारी है कि ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई कर भरोसा कायम रखें। नौदा में हुमायूं कबीर द्वारा लगाए गए आरोप और खैराशोल में ईवीएम गड़बड़ी की शिकायतें केवल स्थानीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यापक चुनौती की ओर इशारा करती हैं, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता को लगातार परखा जाता है। लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास की एक सतत प्रक्रिया है, जिसे बनाए रखना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद, यह स्वीकार करना होगा कि इस बार केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की तैनाती ने कई संभावित बड़ी घटनाओं को रोका है। इसी तरह बीरभूम के खैराशोल और अन्य इलाकों में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जो हिंसक झड़पें हुईं, वे तकनीकी विश्वास के संकट को सामने लाती हैं। जब मतदाता यह महसूस करने लगते हैं कि उनका बोट सही जगह नहीं जा रहा है, तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है। हालांकि इस तरह की शिकायतों की सत्यता की जांच जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि चुनाव आयोग और प्रशासन इस तरह की आशंकाओं को तुरंत और पारदर्शी तरीके से दूर करें। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास लंबा और जटिल रहा है। 1977 में वाम मोर्चा के सत्ता में आने के बाद से लेकर पंचायत राजनीति तक, सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई ने कई बार हिंसक रूप लिया। पार्टी सोसाइटी जैसी अवधारणाएं इसी पृष्ठभूमि में जन्मी, जहां राजनीति ने सामाजिक ढांचे को पूरी तरह प्रभावित किया। 1993 की कोलकाता फायरिंग, सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन, और 2011 के बाद के राजनीतिक बदलाव इन सभी घटनाओं ने यह दिखाया कि बंगाल की राजनीति में टकराव एक स्थायी तत्व बन चुका था। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उम्मीद थी कि हिंसा की संस्कृति में कमी आएगी, लेकिन 2018 के पंचायत चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव ने इस उम्मीद को पूरी तरह साकार नहीं होने दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इस दिशा में संकेत करते हैं कि राजनीतिक हत्याओं के मामले में पश्चिम बंगाल लंबे समय से शीर्ष राज्यों में रहा है। हालांकि इन आंकड़ों पर अक्सर बहस होती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे परिदृश्य में 2026 के पहले चरण में अपेक्षाकृत कम हिंसा होना एक सकारात्मक संकेत जरूर है। खासकर यह तथ्य कि अब तक किसी बड़ी जानलेवा भटना की खबर नहीं आई है, राहत देने वाला है। जहां पहले चुनावी हिंसा आम बात होती थी, वहां अच नियंत्रण और सतर्कता दिखाई दे रही है। यह सुधार लोकतांत्रिक संस्थाओं के मजबूत होने का संकेत है। लेकिन छिटपुट झड़पें, बमबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। मगर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव यह भी दिखाता है कि लोकतंत्र में सुधार धीरे-धीरे ही संभव है। हिंसा में कमी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण चुनाव अभी भी एक लक्ष्य है, जिसे हासिल करना बाकी है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक जागरूकता तीनों का समन्वय जरूरी है। हालांकि इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है, 2021 के विधानसभा चुनाव में 83.17 और 2016 विधानसभा चुनाव 82.66 प्रतिशत मतदान हुआ था, इस बार यह आंकड़ा 92 या 93 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि बंपर वोटिंग का फायदा किसे होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की राय अक्सर इस मुद्दे पर बंटी रहती है। एक पक्ष का मानना है कि उच्च मतदान प्रतिशत आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, यानी लोग बदलाव चाहते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं। यदि इस तर्क को मानें, तो यह भाजपा के पक्ष में जा सकता है, जो खुद को परिवर्तन का विकल्प बताती रही है। वहीं दूसरा पक्ष यह मानता है कि अधिक मतदान का मतलब यह भी हो सकता है कि सत्तारूवु दल के समर्थक अपने आधार को मजबूत करने के लिए अधिक संख्या में मतदान कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पकड़ को देखते हुए यह तर्क भी कमजोर नहीं है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा है, वहां सत्तारूढ़ दल के समर्थन में अधिक मतदान देखा जा सकता है।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य के लोगों ने एसआईआर के विरोध में वोटिंग किया है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस बंपर मतदान को अपने-अपने तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं। तृणमूल इसे अपनी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा इसे बदलाव की इच्छा और सत्ताविरोधी लहर का संकेत बता रही है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं हो सकती है, जिसका फैसला केवल मतगणना के दिन ही स्पष्ट होगा। अंतत:, यह कहा जा सकता है कि 89.93 प्रतिशत मतदान पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

पोषण निगरानी ऐप: कुपोषण के समाधान के लिए डेटा का उपयोग

प्रो. लिंडसे जैक्स

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें डैशबोर्ड से निर्णय की ओर और गणना से देखभाल की ओर बदलाव करने की आवश्यकता है। अंतर्निहित संकेत, सरल चेकलिस्ट और चेतावनी; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमजोर या गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बाद की कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आरसीएच 2.0 पोर्टल के डेटा के साथ एकीकरण, समन्वय की साथ की गयी घर की यात्रा के जरिये रेफरल फॉलो-अप को और भी मजबूत कर सकता है।

हममें से कई लोग अपने डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते हुए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डेटा समय के साथ हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करेंगे, जोखिमों की शुरुआत में ही पहचान कर लेंगे और समय पर कार्रवाई को निर्देशित करेंगे। डिजिटल प्रणालियाँ केवल डेटा संग्रह के कारण ही नहीं, बल्कि जानकारी को निर्णय और बेहतर देखभाल में बदलने में मदद करने की वजह से सबसे बेहतर काम करती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किए जाने के बाद, पोषण निगरानी ऐप ने पोषण सेवा अदायगी डेटा को अधिक कार्रवाई-योग्य बनाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि बाल विकास और पोषण सेवाओं को दर्ज करने और समीक्षा करने में अधिक गंभीरता और निरंतरता लाना है। पोषण निगरानी में नियमित रूप से एकत्र किए गए वृद्धि डेटा को अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के लिए सार्थक निर्णयों में बदलने की क्षमता है। मासिक वृद्धि निगरानी-यदि सही ढंग से मापी जाए और लगातार रिकॉर्ड की जाए-तो जोखिम के शुरुआती संकेत प्रदान कर सकती है। एक एकल, निरंतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वृद्धि रुझानों को पूरक पोषण उपायों से जोड़ने में मदद कर सकता है, जैसे घर ले जाने वाला राशन, देखभाल करने वालों का परामर्श और गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करना आदि।

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें डैशबोर्ड से निर्णय की ओर और गणना से देखभाल की ओर बदलाव करने की आवश्यकता है। अंतर्निहित संकेत, सरल चेकलिस्ट और चेतावनी; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमजोर या गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बाद की कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आरसीएच 2.0 पोर्टल के डेटा के साथ एकीकरण, समन्वय की साथ की गयी घर की यात्रा के जरिये रेफरल फॉलो-अप को और भी मजबूत कर सकता है।

वर्तमान में, एकत्रित वृद्धि डेटा एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। मापन प्रथाओं और प्रणाली समर्थन में सुधारों के साथ, यह समय पर निर्णय लेने में भरोसेमंद जानकारी प्रदान कर सकता है। सटीक निर्णय मूलभूत चीज़ों को ठीक करने पर निर्भर करते हैं-भरोसेमंद मापन, सही तकनीकें और कार्यात्मक उपकरण। यदि किसी बच्चे की ऊँचाई या वजन एक महीने में असामान्य रूप से बदलता है, तो प्रणाली को सत्यापन या पुन: मापन का संकेत देना चाहिए। ऐप में शामिल छोटे माइक्रो-वीडियो देखभाल के स्थल पर वजन पैमाने और लंबाई बोर्ड के सही उपयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में माप-संकेत वाले और कार्यात्मक उपकरण मौजूद हों। ये मूलभूत बातें वृद्धि निगरानी डेटा की उपयोगिता को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

पोषण निगरानी डेटा का विश्लेषण डैशबोर्ड से निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव का भी समर्थन कर सकता है। सबसे पहले, हमें पता होना चाहिए कि कुपोषण की सबसे अधिक संभावना कब होती है-किस उम्र में और वर्ष के किन महीनों में। क्या यह जन्म के समय होता है? या क्या 0 से 3 महीने या 3 से 6 महीने महत्वपूर्ण हैं, जब माताओं को केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? या यह 6 महीने से 1 साल के दौरान होता है, जब पर्याप्त, उचित और सुरक्षित पूरक आहार की आवश्यकता होती है? पोषण निगरानी डेटा के विश्लेषण से हमें उन बच्चों के बारे में और ज़्यादा जानने में भी मदद मिल सकती है जो कुपोषण से ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ खास ज़िलों के बच्चों में ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है? क्या खरीफ फसल की कटाई वाले महीनों के दौरान बच्चों के ठीक होने की संभावना अधिक होती है? इसी तरह, ऐसे विश्लेषण हमें उन बच्चों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं जो अपने पूरे बचपन के दौरान बार-बार या लगातार कुपोषण का शिकार होते रहते हैं। क्या ये वे बच्चे हैं, जो जन्म के समय से ही कुपोषण के शिकार थे और बाद में भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए? क्या ये वे बच्चे हैं, जिन्हें घर ले जाने वाला राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है? इस तरह की जानकारी होने पर, स्थानीय स्तर पर पोषण सेवा अदायगी को बेहतर बनाया जा सकता है। डेटा पर भरोसा बढ़ाना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कार्यभार में कमी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रणाली में विश्वास बढ़ने के साथ, अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में ऐप का उपयोग करने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि, कई जगहों पर, संचार-संपर्क की समस्याओं या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण डिजिटल प्रविष्टि के साथ-साथ कागजी रजिस्टर भी रखे जाते हैं। ऑफ़लाइन कार्यक्षमता को मजबूत करना, डेटा की विश्वसनीयता में सुधार करना और डिजिटल-प्रथम कार्यप्रवाह पर स्पष्टता प्रदान करना, सेवा स्थल पर डेटा प्रविष्टि की ओर बदलाव को गति देने और दोहरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। प्रणाली को परिष्कृत करने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि ऐप उनके काम में सहायक हो। पोषण निगरानी ऐप समय पर और सोच-समझकर फ़ैसले लेने में मदद करने वाला एक भरोसेमंद उपकरण है। इसकी असली ताकत जोखिम की जल्द पहचान करने, तेज़ी से बाद की कार्रवाई करने और पोषण सेवाओं के बेहतर तालमेल को सक्षम बनाने में है। आखिरी छोर की ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर बनाया गया और डेटा की गुणवत्ता व इसके इस्तेमाल में हुए लगातार सुधारों से और मज़बूत बनाया गया पोषण निगरानी ऐप, सिर्फ़ एक निगरानी उपकरण ही नहीं, बल्कि पोषण सेवा अदायगी को मज़बूत बनाने का एक सार्थक उपाय भी है।

(लेखिका एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण की प्रोफेसर हैं।)

नक्सलियों से मध्यप्रदेश भी हुआ मुक्त

डॉ. विजय अग्रवाल

पिछले लगभग पाँच दशकों से हमारे देश की गले की हड्डी की तरह अटके हुए नक्सलियों से अंतत: भारत ने मुक्ति की घोषणा कर दी है। निश्चित तौर पर यह घोषणा मध्यप्रदेश के लिए किसी भी रूप में कम मायने नहीं रखती है। मध्यप्रदेश ने नक्सलियों के दंश को अपने दो स्वरूपों में बर्दाश्त किया है। इसका पहला रूप वह था, जब सन् 2000 से पहले छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक थे। सन् 2000 में राज्य के विभाजन के बाद नक्सलियों से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। किन्तु उसकी कुछ जड़ें मध्यप्रदेश में भी मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ के तीन सीमावर्ती जिले बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी इससे प्रभावित होते रहे। इन नक्सलियों की कार्यावधि और हिंसात्मक गतिविधियों ने न केवल यहाँ के रहने वालों के नाक में दम कर रखा था, बल्कि वे इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के विकास के कामों के दुश्मन बने हुए थे।

पिछले कुछ सालों से मध्यप्रदेश की सरकार ने 'पुनर्वास से कायाकल्प' नीति का सहारा लिया। तब से वहाँ बदलाव की बयार की तेजी से बहने की शुरुआत हुई। सीआरपीएफ के नौजवानों के साथ स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे। इन सबका मिला-जुला प्रभाव यह रहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल के दिसम्बर में एक प्रकार से इन तीन जिलों को नक्सलियों से मुक्त जैसा घोषित कर दिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद केन्द्र सरकार की इस घोषणा ने उसे और भी अधिक मजबूत बना दिया। सामान्यतया किसी भी क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के दो मुख्य मानक माने जाते हैं। पहला यह कि वहाँ उस संगठन का कोई कार्यकर्ता शेष न हो। दूसरा यह कि संगठन के कार्यकर्ताओं का कार्यक्षेत्र पूरी तरह से सिमट जाए। जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, यह कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि वहाँ ये दोनों मानक शत-प्रतिशत लागू होते हैं। लेकिन इसमें अब कोई दो मत नहीं है कि संगठन के सारे प्रमुख नेता इस तरीके से या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब उनका अस्तित्व अपनी अंतिम साँसे ले रहा है। जहाँ तक मध्यप्रदेश का सवाल है, यहाँ के ये तीन जिले इससे प्रभावित जरूर थे। लेकिन यह संगठन का प्रमुख कार्यक्षेत्र नहीं था। इस आधार पर नक्सलियों से मुक्त होने के मामले में छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्यप्रदेश को अधिक सटीक वक्तव्य वाला राज्य कहा जा सकता है। देश को और राज्य को नक्सलियों से मुक्त करना आसान काम नहीं था। लेकिन इस काम की सफलता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यदि राजनैतिक इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो कठिन से कठिन एवं जटिल से जटिल परिस्थितियों पर जीत पाई जा सकती है। यह जीत पा ली गई है। लेकिन यह जीत बनी रहे इसे, गारंटीशुदा स्थिति की तरह लेना गलत होगा।। बहुत जरूरी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा के इंतजाम बने रहें।साथ ही साथ वहाँ आर्थिक विकास के काम भी जारी रहने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही राज्य के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन जिलों में कृषि, पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं. प्रेस सूचना ब्यूरो में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर थे।85 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं।)

खास बात

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ममता दीदी?

समय का पहिया किस तरह से घूमता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी से, जो स्वयं नारी शक्ति हैं। महिलाओं की आड़ में भाजपा लड़ रही है। कहते हैं, लोहा से लोहा काटा जाता है। इसी तर्ज पर चुनाव प्रचार के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए ममता दीदी को चुनौती दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता दीदी से महिलाओं की आड़ लेकर चुनाव लड़ रही है। इसे कहते हैं, समय की बलिहारी।

दर-दर भटक रही है, नारी शक्ति

इन दोनों देश में नारी शक्ति को लेकर सभी राज्यों के सभी जिलों में भाजपा के प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा नेता, कार्यकर्ता सभी नारी वंदन कर रहे हैं। महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। नौकरी खत्म हो गई है। वह पलायन करके अपने घर वापस लौट रही हैं।खाना नहीं बन पा रहा है। मजदूरी नहीं मिल रही है।जगह-जगह महिला और पुरुष श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है। हर आंदोलन में महिलाएं बड़ी संख्या में दिख रही हैं। पेट की आग तो उमकी बुझ नहीं रही है। गरीब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर, विधायक और सांसद बनाने का झुनझुना बजाया जा रहा है। महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं, पहले वह पेट की आग बुझायें। या सांसद विधायक बनने की लाइन में लग जाएं।

ब्रिक्स, जी-20 के देश और विश्व गुरु भारत?

1 माह से अधिक का समय हो गया है। सारी दुनिया के देश तृतीय विश्व युद्ध की आशंका से भयाक्रांत हैं। पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद महंगाई, आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट दुनिया के सभी देशों में देखने को मिल रहा है। जी-20 और ब्रिक्स संगठन ने भारत से बैठक बुलाने की गुहार लगाई है। बैठक तो भारत ने बुलाई नहीं, उल्टे भारत ने अमेरिका और इजरायल के साथ संबंधों को लेकर जिस तरह की चुप्पी साथ रखी है।उसके कारण भारत अलग-थलग पड़ गया है। भारत की जो विश्व गुरु की साख थी।उसमें पलीता लग गया है। कहावत है, थोथा बड़ा की लवार लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जब समय आता है, तो चुप्पी साधकर खिसक जाते हैं। इस कठिन समय में भारत की यही छवि दुनिया के देशों में बन गई है। भाजपा संरक्षक मंडल के वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी को सामने आकर कहना पड़ा।भारत पहिले विश्व गुरु था, अब नहीं है।

दलाल पाकिस्तान भारी पड़ा भारत पर

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्तता को दलाली बताया था। पूंजीवादी युग में दलालों की सबसे बड़ी ताकत होती है। बिना दलाल के कुछ होता भी नहीं है। पाकिस्तान इसे समझता था।भारत को मौका नहीं मिला। हर सौदे में दलाल की जरूरत होती है। रिश्वत के लेनदेन में भी बिचौलिया, दलाल ही बनता है। जय शंकर को यह बात अच्छे से पता थी। एक दलाल दूसरे दलाल को घुसने नहीं देता है।

राशिफल

शुभ संवत 2083, शाके 1948, सौम्य गोष्ठ, वैशाख शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, गुरु उदय पूर्वे, शुकास्त, पश्चिमे तिथि, दसवी, रविवार, मघा नक्षत्रे, वृण योगे, तैतिल करणे, सिंह की चंद्रमा, मूल समाप्त रात्रि 10/39 से रवियोग 42/33 तथापि पूर्व दिशा की यात्रा शुभ उत्तम फलदायी होगी।

आज जन्म लिए बालक का फल: आज जन्म लिया बालक योग्य, बुद्धिमानी, चपल, चतुर, चंचल, स्वाभिमानी, कुशल वक्ता-अधिवक्ता, प्रशासक, अधिकारी, शिक्षक, लेक्चरार, प्रोफेसर, प्रिंसपल, योगी-भोगी, प्रशासनिक अधिकारी, धनी-मानी होगा।

मेष राशि- तनाव व उदर रोग, मित्र लाभ, राजभय तथा दाम्पत्य जीवन पूर्ण संतोषप्रद रहेगा।

वृष राशि- शत्रुभय, शुभ मंगल कार्य, विरोध मामले-मुकदमे में प्राय: जीत की संभावना है।

मिथुन राशि- कुसंग हानि, रोगभय, यात्रा, उद्योग, व्यापार की स्थिति लाभ-हानि की बनी ही रहेगी।

कर्क राशि- पराक्रम, कार्यसिद्धी, व्यापार लाभ, खेती व गृह कार्य में व्यवस्था अवश्य बढ़ेगी।

सिंह राशि- तनावपूर्ण स्थिति से बचें, विरोध, चिन्ता, उद्योग, व्यापार से लाभ, कार्य सफल होंगे।

कन्या राशि- भूमि-लाभ, स्त्री-सुख, प्रगति, उद्योग-व्यापार में अड़चने होगी, ध्यान अवश्य रखें।

तुला राशि- प्रगति, वाहन भय, भूमि-लाभ, कलह, व्यर्थ अनाप-शनाप खर्च से परेशानी होगी।

वृश्चिक राशि- कार्यसिद्धी, विरोध, लाभ, कष्ट, हर्ष होगा, व्यापार में सुधार अवश्य ही होगा।

धनु राशि- यात्रा से हानि, मातृ-पितृ कष्ट, व्यय होगा, लिखा-पढ़ी व शिक्षा जगत से सुख होगा।

मकर राशि- शुभ कार्य, वाहनादि भय, नौकरी की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, ध्यान दें।

कुंभ राशि- अभीष्ट कार्य सिद्धी, राजभय, कार्य बाधा, धार्मिक व कुछ अच्छे कार्य बनेंगे।

मीन राशि- अल्प हानि, रोगभय, सम्पत्ति का लाभ, मित्रों व पारिवारिक लोगों से सावधान रहें।

पीएल गौतमाचार्य

दैनिक पंचांग

26 अप्रैल 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	मेष में	वृष	06.38 बजे से
चंद्र	सिंह में	मिथुन	08.36 बजे से
मंगल	मीन में	कर्क	10.49 बजे से
बुध	मीन में	सिंह	13.05 बजे से
गुरु	मिथुन में	कन्या	15.17 बजे से
शुक्र	वृष में	तुला	17.28 बजे से
शनि	मीन में	वृश्चिक	19.43 ब.से
राहु	कुंभ में	धनु	21.59 बजे से
केतु	सिंह में	मकर	00.04 बजे से
राहुकाल 4.30 से 6.00 बजे तक		कुंभ	01.50 बजे से
		मीन	03.23 बजे से
		मेष	04.54 बजे से

रविवार 2026 वर्ष का 116 वा दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास वैशाख **पक्ष** शुक्ल
तिथि दशमी 18.07 बजे को समाप्त।
नक्षत्र मघा 20.27 बजे को समाप्त।
योग वृद्धि 22.28 बजे को समाप्त।
करण तैतिल 06.14 बजे तदनन्तर गर 18.07 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 8.5 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 13° 27'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872691
जूलियन दिन 2461156.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1447
महीना जिल्काद
तारीख 08
विशेष महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
उद्वेग	05.56 से	07.23 बजे तक	शुभ	05.36 से	07.09 बजे तक
चर	07.23 से	08.51 बजे तक	अमृत	07.09 से	08.41 बजे तक
लाभ	08.51 से	10.18 बजे तक	चर	08.41 से	10.14 बजे तक
अमृत	10.18 से	11.46 बजे तक	रोग	10.14 से	11.46 बजे तक
काल	11.46 से	01.14 बजे तक	काल	11.46 से	01.19 बजे तक
शुभ	01.14 से	02.41 बजे तक	लाभ	01.19 से	02.51 बजे तक
रोग	02.41 से	04.09 बजे तक	उद्वेग	02.51 से	04.24 बजे तक
उद्वेग	04.09 से	05.36 बजे तक	शुभ	04.24 से	05.53 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

महापौर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर बैठक

निर्धारित मापदंड अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

इंदौर ■ निसं

आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा निगम के समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों, सीएसआई एवं संबंधित अधिकारियों के साथ सीटी बस ऑफिस में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल, अपर आयुक्त प्रखर सिंह सहित समस्त स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान महापौर भार्गव ने स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी जोन एवं वार्ड स्तर पर अधिकारी प्रातःकालीन समय में फील्ड में उपस्थित रहकर सफाई व्यवस्था का सतत निरीक्षण करें तथा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होना सुनिश्चित करें। महापौर भार्गव ने स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में भी निर्धारित स्वच्छता मापदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि इंदौर के स्वच्छता अभियान में शहर के जागरूक नागरिकों के साथ-साथ निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

उन्होंने आगे कहा कि आगामी दिनों में वे स्वयं महापौर परिषद सदस्यों एवं पार्षदों के साथ फील्ड में उपस्थित रहकर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करेंगे तथा निरंतर जोन एवं वार्ड क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे।

स्वच्छता अभियान को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 26 अप्रैल को शहर के समस्त हॉस्टल एसोसिएशन के साथ स्वच्छता के मापदंड एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त शहर में मच्छरों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

महापौर भार्गव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समन्वय के साथ कार्य करते हुए इंदौर को पुनः देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाए रखने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

शिल्पू भदौरिया हत्याकांड

10 साल बाद इंसाफ

3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

इंदौर ■ निसं

इंदौर के होटल लेमन ट्री में दस साल पहले हुए चर्चित शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में तीन आरोपियों को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी ग्वालियर के निवासी हैं। उन्हें कोर्ट ने युवती की हत्या के लिए दोषी माना है। 7 अगस्त 2016 को शिल्पू भदौरिया होटल की चौथी मंजिल पर रुकी थी। उसका शव रात को ग्राउंड फ्लोर पर मिला था। पहले पुलिस ने आत्महत्या मानकर जांच की, लेकिन बाद में पता चला कि होटल में तीन युवक भी आए थे और उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो शरीर पर चोट के निशान मिले। यह भी स्पष्ट हुआ कि चौथी मंजिल से गिरने से पहले उसका गला दबाया गया था। पुलिस ने आशुतोष जोहरे, शैलेंद्र सारस्वत और नीरज दंडोतिया निवासी ग्वालियर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले शिल्पू का गला दबाया था, फिर आत्महत्या दिखाने के लिए उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया था।

इस मामले में पुलिस ने हत्या के छह माह बाद चार्जशीट पेश की और 9 साल तक केस कोर्ट में चला। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए उम्रकैद और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपियों ने शिल्पू को पहले शराब पिलाई थी, फिर उसका गला दबाया। शिल्पू ने बचने के लिए संघर्ष किया। उसके नाखूनों में आरोपियों की त्वचा भी मिली, जो अहम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश हुई। शिल्पू का गला दबाने के बाद उसे फेंक दिया गया था।

आयुक्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

इंदौर ■ निसं

आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा आज प्रातःकाल नगर निगम के झोन क्रमांक 07 अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त अर्थ जैन, झोन नियंत्रणकर्ता अधिकारी श्रीमती टीना सिसोदिया, झोनल अधिकारी सुनील जादौन, स्वास्थ्य अधिकारी मनोहर गौसर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त सिंघल ने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए झोन क्रमांक 07 के वार्ड क्रमांक 29, 32, 34 एवं अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने वाटर बॉडी, बस स्टॉप, सीटीपीटी (सार्वजनिक शौचालय), उद्यान, बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

आयुक्त द्वारा स्कीम नंबर 54 में व्यावसायिक बाजार क्षेत्र, विजयनगर चौराहा, वार्ड क्रमांक 34 में स्कीम नंबर 114 में स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान, रानी लक्ष्मी बाई उद्यान, महाराणा प्रताप उद्यान, ग्लोबल गार्डन, विभिन्न टूरिस्ट प्लेस, कालका माता मंदिर, आनंद मोहन माथुर सभागृह, सीटीपीटी, कुएं-बावड़ी सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित स्थानों पर साफ-सफाई, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था, डस्टबिन की उपलब्धता, शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव की स्थिति का अवलोकन किया।

आयुक्त सिंघल द्वारा निरीक्षण के दौरान उद्यानों में हरियाली बनाए रखने,सिंचाई के लिए ट्रीटेड पानी का उपयोग करने तथा इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जलस्रोतों को सहजने के क्रम में वार्ड के कुएं बावड़ी का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान हुए जलस्रोतों की निरंतर साफ सफाई एवं रखरखाव करने के भी निर्देश दिए । आयुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

इंदौर में गहराता जल संकट

तालाबों का स्तर घटा, टैंकरों पर बढ़ी निर्भरता

इंदौर ■ निसं

शहर के तालाबों की स्थिति (पानी की गहराई फीट में)	
यशवंत सागर	13 फीट
बिलावली	10.4 फीट
छोटा बिलावली	0 फीट
बड़ा सिरपुर	10 फीट
छोटा सिरपुर	14 फीट
पिपल्याहाना	7.3 फीट

इंदौर में गर्मी के तेवर दिन-ब-दिन तीखे होते जा रहे हैं और शहर की जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शहर के बड़े हिस्से की प्यास बुझाने वाले यशवंत सागर तालाब में 13 फीट पानी बचा हुआ है। इस तालाब से हर दिन 30 एमएलडी पानी लिया जा रहा है। देवधरम टेकरी पर फिल्टर करने के बाद इस पानी को शहर की पांच टंकियों में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। पहले तालाब से 35 एमएलडी पानी लिया जाता था। इस तालाब की कुल क्षमता 19 फीट है।

शहर के आठ हजार से ज्यादा सरकारी बोरिंगों में से कई बोरिंग सूख चुके हैं, जबकि ज्यादातर बोरिंगों में पानी का स्तर कम हो गया है। यही हाल निजी बोरिंगों का भी है। इस कारण शहर में पानी की मांग बढ़ गई है। पहले कई परिवारों की पानी की जरूरत निजी बोरिंगों से पूरी हो जाती थी, लेकिन अब वे भी नर्मदा जल पर निर्भर हो गए हैं।

शहर में टैंकरों की संख्या बढ़ा दी गई है। 85 वार्डों में टैंकर लगाए गए हैं। जिन वार्डों का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है, वहां दो-तीन टैंकर लगाए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम के 40 से ज्यादा सरकारी टैंकरों से भी पानी बांटा जा रहा है। इन किराए के टैंकरों पर निगम हर माह दो से तीन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। मई माह तक शहर में टैंकरों के माध्यम से जल वितरण जारी रहेगा। शहर के 20 प्रतिशत इलाकों में अभी नर्मदा लाइन नहीं पहुंची है। वहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। शहर के सीमावर्ती इलाके इसमें शामिल हैं। बायपास और रिंग रोड की कॉलोनियों के अलावा लसुड़िया क्षेत्र के इलाकों में जल संकट ज्यादा है। वहीं शहर के बाणगंगा, चंदन नगर, एरोड्रम रोड, प्रजापत नगर और अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी नल कम दबाव से आ रहे हैं। कई इलाकों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है।

मालवा-निमाड़ में अप्रैल में ही हीटवेव जैसे हालात

पारा 43°C पार, राहत के आसार नहीं

मालवा और निमाड़ अंचल में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और पूरा क्षेत्र भट्टी की तरह तप रहा है। शुक्रवार को रतलाम में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो क्षेत्र में सबसे अधिक रहा। इसी तरह धार में 42.4, खरगोन में 42.0, खंडवा और उज्जैन में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में भी पारा 41.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक इस तपती गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। शनिवार को भी इंदौर में सुबह से भीषण गर्मी है। सुबह 7 बजे से ही तेज धूप लग रही है और 11 बजे ही पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है।

इंदौर शहर में शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा जहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इस साल यह पहली बार है जब पारा 41 डिग्री के स्तर को पार कर गया है। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल से ही शहर का तापमान लगातार 39 से 40 डिग्री या उससे अधिक बना हुआ है। शुक्रवार की दोपहर हवाओं की स्थिति लू जैसी रही जहां 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले गर्म थपेड़ों ने लोगों को झुलसाने का अहसास कराया।

इंदौर में यातायात आरक्षक अंकित तोमर ने लगाई फांसी

इंदौर ■ निसं

इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के चौथी पलटन पुलिस क्वार्टर की पहली मंजिल में रहने वाले यातायात पूर्वी में पदस्थ आरक्षक अंकित तोमर ने अपने ही रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात, मौके पर एफएसएल की टीम और ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। एसीपी ने बताया कि थाना मल्हारगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौथी पलटन पुलिस क्वार्टर की पहली मंजिल में रहने वाले यातायात पूर्व में पदस्थ आरक्षक अंकित तोमर अपने रूम में मृत अवस्था में मिला है, मौके पर जांच पता चला है कि मृतक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम व पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मृतक अंकित तोमर के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला है, कि मृतक यातायात आरक्षक अंकित तोमर रात 10:00 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौटा था। एसीपी ने बताया कि मृतक का दिल्ली पुलिस में आरक्षक पद पर चयन भी हुआ था और 4 महीने बाद वह जॉइनिंग करने वाले थे।

इंदौर में स्कूलों की मनमानी पर सख्ती

कॉपी-किताब मोनोपोली के खिलाफ एफआईआर

इंदौर ■ निसं

इंदौर के निजी स्कूलों में कॉपी, किताब, फीस और ड्रेस को लेकर बनाई गई मोनोपोली के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान निरंतर जारी है। हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशासन द्वारा की गई इन कार्रवाइयों से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।

वहीं प्रशासन की सक्रियता के साथ ही हेल्पलाइन पर स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में प्रशासन ने तीन प्रमुख संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे जनमानस में जागरूकता बढ़ी है।

प्रशासन द्वारा की गई पहली बड़ी कार्रवाई गांधीनगर स्थित गुरुकुल शांति (वर्ल्ड पीस स्कूल) के विरुद्ध हुई है। यहां के संचालक और प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों को केवल स्कूल परिसर के भीतर स्थित दुकान से ही किताबें खरीदने के लिए विवश कर रहा है। जांच में पाया गया कि वे पुस्तकें बाजार की अन्य दुकानों पर उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। जब जांच दल मौके पर पहुंचा, तो प्राचार्य ने पुस्तकों की व्यवस्था से जुड़े तथ्यों को लिखित में स्वीकार किया। प्रशासन ने इसे पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन मानते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 223 के तहत थाना गांधीनगर में मामला दर्ज कराया है।

दूसरी कार्रवाई स्कीम नंबर 78, विजय नगर स्थित डेजी डेल्स स्कूल और विजय नगर क्षेत्र की प्रिंसेस रेजिडेंसी में संचालित इंदौर बुक वाला पर की गई है। इन दोनों संस्थानों के संचालकों के विरुद्ध विजय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि डेजी डेल्स स्कूल द्वारा अभिभावकों पर एक ही दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकें बाजार में कहीं और उपलब्ध नहीं थीं और केवल इंदौर बुक वाला पर ही मिल रही थीं। गठित जांच दल ने इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की।

तीसरी कार्रवाई महू क्षेत्र के श्री साईं एकेडमी स्कूल और विद्या श्री स्टेशनरी के खिलाफ की गई है। यहां की शिकायतों में यह बात सामने आई थी कि स्कूल संचालक और स्टेशनरी दुकानदार आपस में मिलकर अभिभावकों पर महंगी सामग्री खरीदने का दबाव डाल रहे थे।

पानी भरने के विवाद में युवक की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर ■ निसं

इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरी घटना रविदास नगर की है, जहां 24 अप्रैल की सुबह पानी भरने की बात को लेकर चिंताराम राठौर और मोहल्ले के युवक मोहित के बीच विवाद हुआ था। उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन शाम को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने चिंताराम को जोतीबाई फाटक के पास ढाबे पर घेर लिया।

इंदौर में सड़कों की चौड़ाई पर विवाद, सात प्रोजेक्ट अटके

इंदौर ■ निसं

इंदौर नगर निगम द्वारा मास्टर प्लान में प्रावधान की गई सड़कों में से सात सड़कों का निर्माण इन सड़कों की चौड़ाई को लेकर विवाद के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है। निगम के अधिकारी इस बारे में भोपाल से स्पष्ट निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहां से कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं और जनप्रतिनिधि चौड़ाई कम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। पुराने अधिकारी अपने कार्यकाल में चौड़ाई घटाने से इनकार कर चुके हैं।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से इंदौर नगर निगम को 465 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस राशि से नगर निगम को मास्टर प्लान में प्रावधान की गई 23 सड़कों का निर्माण करना है। इनमें जो सड़कें इंदौर शहर के अंदर आ रही हैं उनमें चौड़ाई को लेकर विवाद हो रहा है। जो सड़कें शहर के बाहरी क्षेत्र में हैं उनमें तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होना है, इसलिए काम आसानी से हो रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि जो सात सड़कें उलझ गई हैं वहां जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नागरिकों द्वारा सड़क की चौड़ाई को कम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव के चलते नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारी हो जाने के बावजूद इन सड़कों का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब इन सड़कों के लिए इस तरह का दबाव-प्रभाव बनाया जा रहा हो। जब भी नगर निगम द्वारा इन सड़कों का निर्माण शुरू करने की पहल की जाती है, तब दबाव-प्रभाव शुरू हो जाता है। अब तक तो हमेशा नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त द्वारा इस तरह के किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सड़कों का निर्माण ही शुरू नहीं हुआ। इस समय नगर निगम ने इन सभी सड़कों पर नोटिस की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।

भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं पर विशेष फोकस

सिंहस्थ 2028 : ओंकारेश्वर में 6 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी

इंदौर ■ निसं

अपर प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संजय दुबे ने निर्देश दिए हैं कि सिंहस्थ 2028 के लिए ओंकारेश्वर में किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में सिंहस्थ के व्यस्ततम समय के दौरान अनुमानित दर्शन क्षमता के अनुसार भीड़ प्रबंधन हेतु होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएं। साथ ही आमजन और विशिष्टजन के लिए पृथक कॉरिडोर तथा आपातकालीन चिकित्सा रूट की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पार्किंग क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग पॉइंट, ई-कार्ट, बैटरी संचालित साइकिल और व्हीलचेयर का प्रबंध किया जाए। पैदल यात्रियों के लिए उचित दूरी पर पेयजल व्यवस्था और घाटों के समीप कुंड निर्माण के निर्देश भी दिए गए। दुबे ने टेंडर प्रक्रिया, बजट प्रावधान और वर्तमान में जारी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव दुबे ने कहा कि कुबेर भंडारी और ट्रेंचिंग ग्राउंड पर प्रस्तावित पार्किंग सुविधाओं के लिए मास्टरप्लान के अनुसार वन विभाग की अनुमति शीघ्र प्राप्त की जाए। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि गृह विभाग के जवानों को मंदिर, घाट और पार्किंग जैसे क्षेत्रों के लिए स्पॉट ट्रेनिंग कराई जाए और उन्हें केवल उनके प्रशिक्षण वाले विशिष्ट क्षेत्रों में ही तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के पूर्व उन्होंने स्वयं निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान खण्डवा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी दी कि सिंहस्थ 2028 में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने इस विशाल संख्या को देखते हुए मोरटक्का रेलवे स्टेशन, कोठी से ओंकारेश्वर लेफ्ट बाईपास और ओंकारेश्वर से कोठी राइट बाईपास रोड सहित अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।

आपके द्वारा इस गर्मियों में पंछियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की गई हो और सकोरे भी लगाए गए है जिसमें में प्रति दिन स्वच्छ पानी व दाने को रखता है जिससे पंछी आकर ग्रहण करते है। आप भी फोटो भेजकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।

प्रवीण साहू , 8815555243

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने पर खुशदिल शाह का फूटा गुस्सा

करांची। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज खुशदिल शाह राष्ट्रीय टीम में चयन न होने से गहरे हताश हैं। वर्तमान में पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का प्रतिनिधित्व कर रहे खुशदिल ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए अपनी निराशा व्यक्त की। यह नाराजगी पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा के साथ एक बातचीत के दौरान सामने आई, जहां खुशदिल ने टीम से बाहर रखे जाने पर अपना पक्ष रखा। खुशदिल ने गुरुवार को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में कराची किंग्स को पांच विकेट से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने मात्र 14 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।

श्रीलंका को एकदिवसीय में खिताबी दावेदार बनाना है लक्ष्य : कर्स्टन

कोलंबो। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने अपना पद संभाल लिया है और श्रीलंकाई टीम को 2027 एकदिवसीय विश्वकप के लिए तैयार करने की योजना भी बना ली है। कर्स्टन का कहना है कि वह एकदिवसीय विश्व कप के लिए एक ऐसी मजबूत टीम तैयार करना है, जो खिताब की दौड़ में एक प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आये। कर्स्टन ने टीम को बेहतर बनाने की अपनी रणनीति की जानकारी देते हुए कहा, हम सभी प्रारुप में टीम से बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में विश्वकप के अलावा कई और मुकाबले भी हैं। 2027 का एकदिवसीय विश्व कप अगले साल अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।

आरसीबी आक्रामक अंदाज में खेलती रहेगी:बोबाट

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने कहा है कि उनकी टीम इस सत्र में आगे भी आक्रामक रणनीति से ही खेलती रहेगी। बोबाट ने कहा कि कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है उससे हम सभी उत्साहित हैं। कप्तान टीम की सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से अमल में लाने में सफल हुए हैं। बोबाट ने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी निडर होकर खेल रहे हैं और इसी कारण टीम को आगे भी सफल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हम आक्रामक क्रिकेट ही खेलते रहो मैं चाहता हूं कि हम साहसी बनें। बोबाट ने विशेष रूप से उन अवसरों पर ध्यान देने को कहा है जब साहस की सबसे अधिक जरुरत होती है।

चत्रभुज नरसी स्कूल में अत्याधुनिक शूटिंग एकेडमी शुरू, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट से गुरुमंत्र पाकर खिले युवा खिलाड़ी

ओलंपिक कोच रौनक पंडित की मेंटरशिप में छात्र सीखेंगे सटीक निशाना

इंदौर ■ निसं

इंदौर के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज बनाने के उद्देश्य से ओलंपिक कोच और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रौनक पंडित अब शहर में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। चत्रभुज नरसी स्कूल (सीएनएस) इंदौर ने रौनक पंडित की प्रतिष्ठित मेंटरशिप में अपनी स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पिस्टल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया है। शनिवार को इस एकेडमी की शुरुआत दो दिवसीय पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता के साथ हुई, जहाँ शहर के उभरते निशानेबाजों को सीधे विश्व स्तरीय अनुभव से जुड़ने का मौका मिला।

एकेडमी के मेंटर रौनक पंडित ने शुभारंभ के अवसर पर विद्यार्थियों और पालकों के लिए आयोजित ओपन हाउस सेशन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शूटिंग केवल प्रतियोगिता जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि यह युवाओं में फोकस, धैर्य और आत्मविश्वास विकसित करने का एक सशक्त जरिया है। पंडित ने कहा, इस शुरुआती उम्र में बच्चों को निशानेबाजी से जोड़ना उनके भीतर अनुशासन की नींव रखने जैसा है। मुझे खुशी है कि इंदौर में हम उन मूल्यों को साझा कर पा रहे हैं जो खेल के मैदान के साथ-साथ जीवन में भी काम आते हैं।

ओलंपिक स्टैंडर्ड की सुविधाएं : स्कूल परिसर में स्थापित यह एकेडमी ओलंपिक-स्टैंडर्ड की 10-मीटर शूटिंग रेंज से लैस है। बीसीएम ग्रुप के सहयोग से शुरू हुई इस पहल के बारे में स्कूल के चेयरपर्सन सुजय जयराज और प्रिंसिपल डॉ. जेरिन जैकब ने बताया कि रौनक पंडित जैसे दिग्गज एथलीट का मार्गदर्शन मिलना विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

मुंबई और पुणे के बाद अब इंदौर में भी स्कूल एक ऐसा फ्यूचर-रेडी इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जहाँ शिक्षा और खेल के समन्वय से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। यह एकेडमी न केवल बेहतरीन शूटर तैयार करने का लक्ष्य रखती है, बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और नैतिक इंसान बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी।

विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा से छीनी ऑरेंज कैप, आईपीएल 2026 में बने नंबर वन बल्लेबाज

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का रोमांच अपने चरम पर है, और हर गुजरते मैच के साथ ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस और भी दिलचस्प होती जा रही है। टूर्नामेंट के 34वें मुकाबले में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) की टीमें आमने-सामने उतरीं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ही मैच के बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। इस मैच में विराट कोहली के बल्ले से निकली आतिशी पारी ने न केवल बेंगलुरु को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई, बल्कि किंग कोहली को एक बार फिर रनों के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। इस मैच के बाद आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप लिस्ट पूरी तरह बदल गई है। मैच से पहले जो विराट कोहली टॉप-5 से बाहर थे, अब वह सीधे पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। विराट ने इस सीजन में अब तक 7 मैचों में 328 रन बना लिए हैं और वह फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट के ठीक पीछे सनराइजर्स हैदराबाद के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम है। अभिषेक ने भी इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है और वह 7 मैचों में 323 रनों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। उनके ही साथी और हैदराबाद के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन 7 मैचों में 320 रन बनाकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। हैदराबाद के इन दो बल्लेबाजों और विराट कोहली के बीच रनों का अंतर बहुत कम है।

तनिष्का सेन की घातक गेंदबाजी के आगे पस्त हुई इंदौर की टीम

जेएस आनंद ट्रॉफी पर भोपाल का कब्जा

इंदौर ■ निसं

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित जेएस आनंद महिला सीनियर वनडे इंटर डिवीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भोपाल ने मेजबान इंदौर को 25 रनों से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में भोपाल की सधी हुई बल्लेबाजी और तनिष्का सेन की घातक गेंदबाजी के आगे इंदौर की टीम पस्त नजर आई।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भोपाल की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन मध्यक्रम में सौम्या तिवारी और खुशी यादव ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए हुई 81 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की बदौलत भोपाल ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 177 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। खुशी यादव ने नाबाद 49 और सौम्या तिवारी ने 45 रनों का योगदान दिया, जबकि निकीता सिंह ने 26 रन बनाए। इंदौर की ओर से प्रियंका कौशल और अनादि तागड़े ने 2-2 विकेट लिए।

तनिष्का के पंजे में फंसी इंदौर की टीम:178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंदौर की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही। हालांकि, प्रियंका कौशल ने एक छोर संभालते हुए 56 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिल सका। भोपाल की गेंदबाज तनिष्का सेन ने कहर बरपाते हुए 9.3 ओवर में 4 मेडन रखते हुए महज 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनके इस पंजे की मदद से इंदौर की पूरी टीम 48.3 ओवर में 152 रनों पर ढेर हो गई। निकीता सिंह ने भी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके।

मैच के समापन पर मनमीत आनंद (स्व. जेएस आनंद जी की पुत्रवधू) ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर एमपीसीए की संयुक्त सचिव अरुंधति किरकिरे और मैच ऑब्जर्वर रेखा सोहल पुणेकर मौजूद रहीं। शानदार गेंदबाजी के लिए तनिष्का सेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, इंदौर की जिया जेठवा और भोपाल की राहिला फिरदौस को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फील्डर का पुरस्कार दिया गया।

एलएनसीटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जू-जित्सु प्रतियोगिता

भोपाल ■ निसं

भोपाल एलएनसीटी यूनिवर्सिटी द्वारा एलएनसीटी कोलार में आयोजित पांच दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जू-जित्सु (पुरुष एवं महिला) प्रतियोगिता 2025-26 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबलों के बाद मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन घोषित पदक तालिका के अनुसार मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 13 पदकों के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आरजीयू) ने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मेजबान एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक अपने नाम किए, जिससे विश्वविद्यालय ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने दर्शकों और आयोजकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवॉर्ड महिला वर्ग में स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी की लावण्या को प्रदान किया गया, जबकि पुरुष वर्ग में स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के निवेदन सिंह गुर्जर को यह सम्मान मिला।

जू-जित्सु आत्मरक्षा से संबंधित प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न भार वर्गों में ने-वाज़ा, फाइटिंग सिस्टम, फुल कॉन्टैक्ट, डुओ शो, डुओ क्लासिक एवं मिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। इस खेल में खिलाड़ी अपनी तकनीक, शक्ति, संतुलन और आत्मरक्षा कौशल का प्रदर्शन करते हैं।

मेडल सेरेमनी के समापन अवसर पर डॉ. विनय जोशी सिंह, प्रेसिडेंट, जू-जित्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमित अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी, जू-जित्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया, पंकज पाराशर, संयोजक, आर.के. शर्मा खेल अधिकारी, टीआईटी, पंकज कुमार जैन, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, एलएनसीटी

व्यापार समाचार

निवेशकों को लग सकता है झटका, एक ही एएमसी में निवेश का जोखिम

क्या फ्लैक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में निवेश से मिल रहा दोहरा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच फ्लैक्सी कैप और लार्ज एंड मिड केप फंड्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। कई निवेशक मानते हैं कि दोनों कैटेगरी में निवेश से उनका पोर्टफोलियो सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, लेकिन असल तस्वीर थोड़ी अलग है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इन फंड्स के पोर्टफोलियो में काफी ओवरलैप देखा जा रहा है, खासकर एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के फंड्स में, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। वैल्यू रिसर्च के विश्लेषण में सामने आया है कि करीब 31 फंड पेयर्स में से 16 में 40 प्रतिशत से अधिक स्टॉक्स का ओवरलैप था। इसका मतलब है कि निवेशक अनजाने में एक ही स्टॉक्स में दो बार पैसा लगा रहे होते हैं। बाजार के ?विश्लेषक बताते हैं कि फ्लैक्सी केप फंड्स को बाजार की स्थिति के अनुसार लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में निवेश बदलने की आजादी होती है, जबकि लार्ज एंड ?मिड कैप फंड्स को न्यूनतम 35 फीसदी लार्ज कैप और 35 फीसदी मिड कैप में निवेश करना अनिवार्य है।

हालांकि फ्लैक्सी कैप फंड्स अक्सर लार्ज कैप की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं, जिससे दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो में समानता बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मॉनिटर करें और अलग-अलग एएमसी के फंड्स में निवेश करें, तो सीमित ओवरलैप के साथ भी बेहतर संतुलन बन सकता है। एक ही एएमसी के फ्लैक्सी केप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश करने से एएमसी कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ता है, क्योंकि एएमसी अक्सर एक जैसी निवेश रणनीति अपनाते हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि किसी एक एएमसी में कुल पोर्टफोलियो का 25-30 प्रतिशत से अधिक निवेश न करें।

कच्चे तेल के बाद अब पाम तेल की किल्लत का खतरा

नई दिल्ली। वैश्विक तनावों और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के बीच भारत एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति में संभावित बाधाओं के साथ-साथ अब देश के लिए पाम तेल की उपलब्धता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। भारत दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है, अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया पर निर्भर करता है। हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर संभावित प्रतिबंध लगाने की घोषणा से भारत की खाद्य सुरक्षा पर संकट गहरा गया है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन पाम तेल का उपयोग करता है, जबकि उत्पादन 4 लाख टन से भी कम है। यह देश के कुल खाद्य तेल का 40 फीसदी है, जो सस्ता होने और लंबे समय तक स्थिर रहने के कारण आधे से अधिक परिवारों की रसोई का अभिन्न अंग है। पाम तेल सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। तले हुए चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, केक, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, आइसक्रीम और सभी रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों में इसका व्यापक उपयोग होता है।

35.8 अरब डॉलर पर पहुंचा कारोबार

भारत के कपड़ा निर्यात में आई गिरावट

नई दिल्ली ■ एजेंसी

रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरावट लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में देखने को मिली। कॉटन टेक्सटाइल निर्यात 3.9 प्रतिशत घटा, रेडीमेड गारमेंट्स में 1.4 प्रतिशत की कमी आई और कारपेट निर्यात 5.3 प्रतिशत नीचे रहा। केवल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने मामूली राहत दी, जहां 1.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

रुपये और डॉलर के आंकड़ों में अंतर एक गहरी आर्थिक चिंता: जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि रुपये और डॉलर के आंकड़ों में अंतर एक गहरी आर्थिक चिंता को दर्शाता है। उनका कहना है कि भारत घरेलू मुद्रा में अधिक निर्यात करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार से डॉलर कम कमा रहा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मैन-मेड टेक्सटाइल में रुपये के हिसाब से 3.6 प्रतिशत की बढ़त दिखी, लेकिन डॉलर में यह 0.8 प्रतिशत घट गया। इसी तरह गारमेंट निर्यात रुपये में 2.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि डॉलर में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

क्या है गिरावट की वजह?: श्रीवास्तव के अनुसार, इसका मतलब यह है कि निर्यात में जो बढ़त दिख रही है, वह प्रतिस्पर्धा बढ़ने से नहीं, बल्कि रुपये के कमजोर होने की वजह से है। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रहा है या नए बाजारों में विस्तार नहीं कर पा रहा है। खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में यह चिंता ज्यादा गंभीर है, जहां भारत को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए एक अहम नीति प्रश्न है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (छछ), लॉजिस्टिक्स सुधार और व्यापार सुगमता जैसे कदमों के बावजूद निर्यात वृद्धि क्यों नहीं हो रही। रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि वह तुरंत उन बाधाओं की पहचान करे, जो टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों की निर्यात क्षमता को प्रभावित कर रही हैं।

अमेरिकी घेराबंदी: ईरान पर दबाव, वैश्विक ऊर्जा बाजार में हड़कंप

नई दिल्ली। पश्चिम-एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना ने समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने के लिए 24 अप्रैल को एक ईरानी झंडे वाले जहाज को रोक दिया। यह कार्रवाई अप्रैल की शुरुआत से चल रही ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी रणनीति का हिस्सा है, जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर गहरा असर डाला है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, अमेरिकी गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहे जहाज को रोका। यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अप्रैल की शुरुआत से ही अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को सख्त कर रहा है, जिसके तहत अब तक दर्जनों जहाजों को या तो रोका गया है या उन्हें वापस लौटा दिया गया है।

आरबीआई ने बंधन बैंक पर 41.8 लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय बैंक ने बंधन बैंक और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर अलग-अलग मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई केवाईसी नियमों, जोखिम मूल्यांकन और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन में कमी के कारण की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में अनुशासन बनाए रखना है। आरबीआई ने बंधन बैंक पर 41.8 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) नियमों और जोखिम मूल्यांकन से जुड़े दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन न करने के कारण लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक कुछ खातों की जोखिम श्रेणी की समय-समय पर समीक्षा करने में विफल रहा और निदेशक से जुड़े ऋण को भी मंजूरी दी गई।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मण्डल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए बैंक के लेखों का अनुमोदन किया है.

वित्तीय वर्ष 26 के मुख्य बिन्दु

1. बैंक के निदेशक मण्डल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अनुमोदन के अधीन रु. 5.00 प्रति इक्विटी शेयर (रु.10 प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य का 50%) के लाभांश की संस्तुति की है.

2. वित्तीय कार्यनिष्पादन: वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बैंक का निवल लाभ 18,697 करोड़ था. वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बैंक की ब्याज आय 1,05,992 करोड़ रुपये रही।

3. कारोबार में वृद्धि : बैंक के कुल कारोबार में वर्ष दर वर्ष 5.78% की वृद्धि हुई है, जिसमें सकल अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 9.74% की वृद्धि हुई है और कुल जमाराशि में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2.72% की वृद्धि हुई है. 31 मार्च, 2026 तक बैंक का कुल कारोबार ? 23,85,502 करोड़ है.

4. जमा में वृद्धि: वैश्विक जमाराशि में वर्ष दर वर्ष 2.72% की वृद्धि हुई है. 31 मार्च, 2026 तक बैंक के पास कुल जमाराशि आधार 13,06,891 करोड़ है.

5. रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) क्षेत्र में वृद्धि: बैंक के रैम क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष आधार पर 12.56% की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर रिटेल में 16.75% की वृद्धि और एमएसएमई अग्रिमों में 18.75% की वृद्धि हुई है. घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, रैम अग्रिम 57.49% है.

6. एनपीए में कमी: 31.03.2026 को कुल एनपीए (%) वर्ष दर वर्ष आधार पर 78 बीपीएस की गिरावट के साथ 2.82% रहा तथा निवल एनपीए (%) वर्ष दर वर्ष आधार पर 15 बीपीएस की गिरावट के साथ 0.48% रहा है.

7. सशक्त पूंजी अनुपात: सीआरएआर 31.03.2026 को 18.10% रहा. सीईटी 1 अनुपात दिनांक 31.03.2025 के 14.98% के सापेक्ष 31.03.2026 को सुधार के साथ 15.69% रहा.

'बाजार में अब नई डिजिटल पीढ़ी प्रवेश कर रही है', सेबी प्रमुख बोले

नियामकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि संस्था की विश्वसनीयता सुधारों, मजबूत नियमन और निवेशकों के भरोसे से बनी है। उन्होंने बताया कि भारत के पूंजी बाजार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती दिखाई है।

सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है, जो वर्षों के सुधारों, मजबूत नियमन और निवेशकों के भरोसे से बनी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितताओं और तेजी से बदलती तकनीक के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं।

उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल 1988 को स्थापना के बाद से सेबी ने भारतीय बाजारों को पूरी तरह बदल दिया है। कभी खुले ट्रेडिंग सिस्टम और सीमित पारदर्शिता वाले बाजार अब रियल-टाइम, तकनीक आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, डीमैट व्यवस्था, रोलिंग सेटलमेंट, बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस और मजबूत जोखिम प्रबंधन जैसे कदमों ने इस बदलाव को संभव बनाया।

सीतारमण ने साइबर सुरक्षा पर किया जोर: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सेबी को उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बड़े ब्रोकर पर सफल साइबर हमला राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों को प्रभावित कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा हमला निवेशकों की बड़ी पूंजी मिटा सकता है और आम लोगों का भरोसा भी बुरी तरह हिला सकता है, जिसे दोबारा कायम करने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स साइबर हमलों को पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट, बड़े पैमाने पर और कई मामलों में स्वत: संचालित बना रहे हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिर्फ सेबी ही नहीं, बल्कि उसके तहत आने वाली सभी विनियमित संस्थाओं को भी बेहद सतर्क रहना होगा। हमले के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के साधनों को उससे भी तेज गति से विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 से लागू साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलिएंस फ्रेमवर्क के जरिए सेबी ने सराहनीय काम किया है। यह एक मजबूत आधार है।

केटीएम ने किया ड्यूक श्रृंखला में एक नया और किफायती मॉडल पेश

नईदिल्ली। दोपहिया वाहन बाजार में केटीएम ने अपनी लोकप्रिय ड्यूक श्रृंखला में एक नया और किफायती मॉडल पेश कर ग्राहकों को बड़ा फायदा दिया है। इस नई पेशकश के पीछे 350 घन क्षमता से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होने वाली उच्च कर दर प्रमुख कारण है, जिसके चलते कंपनी ने अपनी रणनीति बदली है। यह नया संस्करण विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो दमदार प्रदर्शन के साथ कम कीमत में एक आधुनिक मोटरसाइकिल चाहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में लू से लोग परेशान, पारा 41.1 डिग्री पर पहुंचा

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में हीटवेव महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कांगड़ा के धर्मशाला, ऊना और कुल्लू के भुंतर में दोपहर के वक्त लू चलने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऊना का अधिकतम तापमान 6 डिग्री ज्यादा उछाकर 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यह इस सीजन का सबसे गर्म दिन है। ऊना का आज तक का अप्रैल महीने का रिकॉर्ड टेंपरेचर 30 अप्रैल 2022 को 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। अन्य शहरों के तापमान में भी सामान्य की तुलना में 4 से 6 डिग्री का उछाल आया है। राहत की बात यह है कि शनिवार से गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसे देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के कुछेक भागों में अंधड़ चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को दोपहर बाद किन्नौर के सांगला में 0.4 मिलीमीटर और कल्पा में 0.1 मिली बारिश हुई। 26 व 27 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। 28 से 30 अप्रैल तक फिर पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों के साथ-साथ ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी तपने लगे हैं। शिमला का तापमान भी सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा के साथ 27.6 डिग्री, मनाली का 4.3 के उछाल के साथ 26.8 सेल्सियस हो गया है।

भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा तैयारियों को जांचने होगी मार्कड्रिल

जोधपुर में बजेंगे सायरन, होंगे हवाई हमले और होगा ब्लैकआउट!

जोधपुर ■ एजेंसी

जोधपुर जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से अगले दो-तीन दिनों में हवाई हमले की चेतावनी और ब्लैकआउट की मॉकड्रिल की जाएगी। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए इस पूर्व निर्धारित अभ्यास में सायरन बजाने और ब्लैकआउट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अभ्यास भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा आलोक रंजन के मार्गदर्शन में किया जाएगा। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में सरकारी विभागों की तत्परता, आपसी समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करना है।

नागरिकों से आग्रह

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि मॉकड्रिल में एयर रेड सायरन बजने या ब्लैकआउट की स्थिति होने पर घबराए नहीं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर इस अभ्यास को सफल बनाने में सहयोग करें।

नागरिक सुरक्षा विभाग ने इसे संस्थागत रूप देने के लिए पूरी योजना तैयार की है। इस मॉकड्रिल में जिला प्रशासन के साथ नागरिक सुरक्षा, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इनके अलावा एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और जोधपुर डिस्कॉम सहित अन्य संबंधित विभागों के बीच कॉर्डिनेशन की टेस्टिंग की जाएगी।

चुनावी सरगर्मी तेज, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी घमासान बढ़ा

अहमदाबाद। गुजरात में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों राजकोट, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और सूरत में सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सक्रिय अभियान चला रही है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार, पार्टी के कुछ नेता और स्थानीय धार्मिक व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप से प्रचार में शामिल दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वादों की भी चर्चा हो रही है। इनमें धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों और सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर आश्वासन जैसी बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें समुदाय विशेष के मतदाताओं से समर्थन की अपील किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पारंपरिक मानी जाने वाली मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए रणनीति बना रही है और स्थानीय स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लॉरेंस गैंग का सदस्य आरजू बिश्नोई गिरफ्तार

चंडीगढ़। चंडीगढ़ से सामने आई एक बड़ी कार्रवाई में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने कुख्यात लॉरेंस गैंग के सदस्य आरजू बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरजू बिश्नोई राजस्थान में एक हत्या के मामले में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अन्य संबंधों की गहन जांच कर रही है। इससे पहले भी एजीटीएफ ने विदेशी गैंगस्टरों द्वारा संचालित एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो विदेशी .30 कैलिबर पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पटियाला जिले के विभिन्न गांवों के निवासियों के रूप में हुई थी। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों में से एक जुलाई 2025 में अबोहर स्थित 'वेयर वेल' शोरूम के मालिक की हत्या में शामिल था। प्रमोद बान ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर विशेष चेकपॉइंट स्थापित किए गए थे।

अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट ने जारी की नई एडवाइजरी

पुरुष धोती-कुर्ता तो महिलाएं साड़ी या सूट पहन करें रामलला के दर्शन

अयोध्या ■ एजेंसी

भीषण गर्मी और बढ़ती श्रद्धालु संख्या के बीच राम मंदिर अयोध्या में दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सुगम बनाने के लिए ट्रस्ट ने नई एडवाइजरी जारी की है। ऑनलाइन दर्शन पास बुकिंग के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है, जबकि समग्र व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील की गई है। गर्मी के कारण दर्शन के समय और भीड़ के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट दोनों स्तर पर व्यवस्थाएं लगातार अपडेट की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे भारतीय परिधान में मंदिर में प्रवेश करें। पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता या धोती-पजामा और महिलाओं के लिए साड़ी, पंजाबी ड्रेस या चूड़ीदार-दुपट्टा पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादा के अनुरूप बताया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दर्शन पास बुकिंग के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। अब सामान्य दर्शन पास के साथ अन्य श्रेणियों के विकल्प भी दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी सुविधा के मुताबिक पास चुनने में आसानी होगी। ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी के मुताबिक सुगम और विशिष्ट दर्शन पास की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए भी पास जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे रामलला और राम दरबार के साथ अन्य मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं।

चिलचिलाती धूप का असर अब मंदिर में दर्शन के समय पर भी साफ दिख रहा है। दोपहर के समय श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, जबकि सुबह और शाम के समय भारी भीड़ उमड़ रही है। बाहर से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले टेढ़ी बाजार से वाहनों को रोक दिया जाता था, जिससे करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना पड़ता था। अब येलो जोन पास मिलने से वाहन मंदिर के पास तक छोड़ सकते हैं, जिससे गर्मी में काफी राहत मिली है।

शिव मंदिर में 29 अप्रैल को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

ट्रस्ट के मुताबिक सुगम दर्शन पास के सभी स्लॉट 8 मई तक पहले ही बुक हो चुके हैं। हालांकि, अधिक से अधिक लोगों को सुविधा देने के लिए दर्शन पास की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि आमजन को भी अधिक अवसर मिल सके। ट्रस्ट के मुताबिक परकोटा स्थित शिव मंदिर में 29 अप्रैल को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

कुंडा में 33 साल से 'अजेय' क्यों हैं राजा भैया? जनसंपर्क, जनता दरबार और स्थानीय प्रभाव बना सबसे बड़ी ताकत, सातवीं बार भी दर्ज की जीत

लखनऊ ■ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है, जहां रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) पिछले 33 वर्षों से लगातार अजेय बने हुए हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया 1993 से इस सीट से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं और अब तक सात बार विधायक बन चुके हैं।

जानकारी अनुसार राजा भैया ने पहली बार 25 वर्ष की उम्र में चुनाव जीता था और तब से यह राजनीतिक यात्रा लगातार जारी है। शुरुआत में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। वर्तमान में उनकी पार्टी का राज्य की राजनीति में भी प्रभाव माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया जा रहा है, कि राजा भैया की जीत का सबसे बड़ा कारण उनका लगातार जनता के बीच बने रहना है। गांव के प्रधानों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पूरे पांच साल क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और हर छोटे-बड़े मुद्दे में हस्तक्षेप करते हैं।

वैसे देखा जाए तो कुंडा में राजा भैया का 'जनता दरबार' भी काफी चर्चित है, जहां वे लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। बताया जाता है कि वे पारिवारिक विवादों से लेकर छोटे झगड़ों तक में फैसले करते हैं, जिन्हें लोग स्वीकार भी करते हैं। यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता मजबूत बनी रहती है। जातीय समीकरणों के बावजूद उनका प्रभाव सभी वर्गों में देखा जाता है। कुंडा की आबादी में अनुसूचित जाति, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता प्रमुख हैं, जबकि उनकी अपनी क्षत्रिय बिरादरी का वोट अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद उनका जनाधार व्यापक माना जाता है।

कुंडा विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी रोचक रहा है। यह कभी कांग्रेस का गढ़ थी और बाद में भाजपा तथा अन्य दलों का प्रभाव भी रहा, लेकिन 1993 के बाद से यह सीट राजा भैया के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार जीत का यह सिलसिला मजबूत स्थानीय नेटवर्क, व्यक्तिगत संपर्क और जनसंपर्क की निरंतरता का परिणाम है, जिसने कुंडा की राजनीति को एक अलग पहचान दी है।

50 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, राघव के बीजेपी में शामिल होने बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर का दावा

आम आदमी पार्टी का कोई क्राइटेरिया नहीं

चंडीगढ़ ■ एजेंसी

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक के अलावा सांसद अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया और उसके बाद पार्टी में शामिल हो गए।

इस घटनाक्रम के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 50 विधायक भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब कोई विचारधारा नहीं होगी तो ऐसा होना तय है।

आम आदमी पार्टी ने बड़ी कंपनियों, बड़े बिजनेस को देखकर विधायक चुने, जिसके बाद उनसे कई फायदे लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में 50 विधायक एक-दूसरे के खिलाफ हो जाएं। वड़िंग ने कहा कि 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से पंजाब में किसी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी सांसद बिना जड़ों वाले हैं और राज्य में उनका कोई मजबूत बेस नहीं है।

बता दें शुक्रवार को राघव चड्ढा ने दिल्ली में कहा था कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सांसदों के साइन वाला एक लेटर और डॉक्यूमेंट राज्यसभा चेयरमैन को सौंपा गया है। उनके अलावा इस पत्र पर सांसद संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल के साइन हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहां यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें भारतीय संविधान के दसवें शेड्यूल के तहत एंटी-डिफेक्शन डिसक्वालिफिकेशन से छूट मिलती है।

असम में सेंचुरी तो पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे: सीएम सरमा

कोलकाता ■ एजेंसी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि इस बार हम असम में सेंचुरी और बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भरोसे से कह सकता हूं कि बंगाल में पहले चरण में ही बीजेपी 110 सीटें जीत चुकी है। उन्होंने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बांग्लादेश से आने वालों के कारण अगले दो दशकों में असम और बंगाल में हिंदू अपना बहुमत का दर्जा खो देंगे।

सीएम हिमंता ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहीं से आएंगे। इससे पश्चिम बंगाल और पूरे देश की जनसंख्या संरचना बदलेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में हर भारतीय की हिस्सेदारी है, क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, खासकर बंगाल और असम पर। उन्होंने कहा कि जब संख्या 50फीसदी से ऊपर जाती है तो शरिया कानून की मांग भी शुरू होती है। धर्मनिरपेक्षता तब तक सुरक्षित है, जब तक जनसंख्या संतुलन बना रहता है। सीएम ममता कहती हैं कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है, लेकिन बीजेपी देश के किसी भी राज्य में गीता या भागवत का शासन लागू करने की मांग नहीं करती।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी को पहले फेज के 152 सीटों में से 125 से 135 सीटें मिलेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इधर चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने लापरवाही बरतने और निष्पक्षता नहीं रखने पर पांच पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। संस्पेड अधिकारियों में एएसपी और एसडीएपीओ भी शामिल हैं।

बिहार में अब 'पुलिस दीदी' महिलाओं और छात्राओं की करेंगी सुरक्षा

पटना ■ एजेंसी

बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब यूपी मॉडल से प्रेरित होकर 'पुलिस दीदी' यानी अभया ब्रिगेड को हाईटेक और ज्यादा सक्रिय बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने इसके तहत 4700 स्कूटी और बाइक खरीदने को मंजूरी दी है, ताकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास मनचलों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। इस योजना पर राज्य सरकार करीब 66.75 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों की गतिशीलता बढ़ाना है, ताकि वे संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। नई व्यवस्था के तहत 'पुलिस दीदी' स्कूटी और बाइक से नियमित गश्त करेंगी। उनकी तैनाती खासकर उन स्थानों पर की जाएगी, जहां छात्राओं की आवाजाही जयादा रहती है और छेड़खानी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर मुख्य फोकस रहेगा। वर्दी और सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। छात्राओं को मौके पर ही सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि छुट्टी के समय छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता रहती है। कई घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए तय किया है कि अब सभी स्कूलों और कॉलेजों के पास 'पिंक स्कूटी' के साथ पुलिस दीदी तैनात रहेंगी।'

स्कूल-कॉलेज के बाहर रहेंगी तैनात, चौधरी ने अपनाया योगी मॉडल

2024 में इसका टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल्स के साथ किया गया था

न्यूक्लियर ट्रायड हुआ पूरा, तीसरी परमाणु पनडुब्बी वापस आई

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत ने 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में आईएनएस अरिदमन, देश की तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को चुपचाप नौसेना में शामिल कर लिया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारत ने इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न नहीं मनाया और कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने एक पोस्ट में कहा शब्द नहीं शक्ति, अरिदमन।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल होना कई मायनो में काफी अहम है। समुद्र में एक एसएसबीएन की मौजूदगी तय करती है कि देश के पास जवाबी हमला करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि भारत पहले

परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करने की नीति को मानता है कि लेकिन हमला होने की स्थिति में तत्काल परमाणु हमला करने की क्षमता भी रखता है।

इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए कम से कम तीन पनडुब्बियों की जरूरत होती है। जिसका मतलब होता है कि एक पनुडुब्बी हमेशा गश्त पर रह सके और बाकी दो पनडुब्बियों का रखरखाव और मरम्मत हो सके। भारत की पहली स्वदेशी एसएसबीएन, आईएनएस अरिहंत को 1980 के दशक में शुरू हुए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया गया था।

6000 टन वाली और 83 एमडब्ल्यू के रिएक्टर से चलने वाली अरिहंत को 2009 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में पानी में उतारी थी और अगस्त 2016 में इसे चुपचाप नौसेना में शामिल कर लिया गया था। नवंबर 2018 में पीएम मोदी ने ट्विटर पर बताया था कि आईएनएस अरिहंत अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल से लौट आई है। इसका मतलब था कि वह परमाणु-हथियारों से लैस मिसाइलों के साथ तैनात थी।

इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जिसमें मिसाइलें, विमान और पनडुब्बियां शामिल हैं अब पूरा हो चुका था। अब भारत जमीन से, आकाश से और समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है और ये क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास ही है। दूसरी एसएसबीएन, आईएनएस अरिघाट (एस3) को अगस्त 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस अरिदमन के शामिल होने से अब भारत को वह तीसरी पनडुब्बी मिल गई है जिसकी उसे समुद्र में लगातार निवारक क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरत थी।

एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि भारत लंबे समय से पृथ्वी और अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि-5 की रेंज सबसे ज्यादा 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे एक कैनिस्टर में रखा जाता है जिससे इसे स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ऑपरेट करना आसान है। 2024 में इसका टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल्स के साथ किया गया था यानी कई वॉरहेड जो अलग-अलग जगहों को निशाना बना सकते हैं। न्यूक्लियर डिलीवरी में सक्षम लड़ाकू विमानों में मिराज-2000, सुखोई-30 और राफेल शामिल हैं।

गृह मंत्री की बयानबाजी चिंता का विषय, टीएमसी को 200 पार की उम्मीद

शाह के बयान पर ममता दीदी का पलटवार: केस करुंगी

कोलकाता ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी माहौल में नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि दीदी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा।

इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे 'अलोकतांत्रिक और हिंसक भाषा' बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि देश के गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में

इस तरह की बयानबाजी चिंता का विषय है और वह इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगी।

वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी चुनावी रैलियों ने बंगाल पर्यटन को अनजाने में बढ़ावा दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में टीएमसी 200 के पार सीटें जीत रही है। चुनाव के इस गर्म माहौल में वोटिंग प्रतिशत, प्रशासनिक मुद्दों और सुरक्षा मामलों को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस जारी है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल चुनाव में बयानबाजी और राजनीतिक टकराव ने मुकाबले को बेहद रोचक और तनावपूर्ण बना दिया है।

भगवान अग्रसेन जी की 26वीं महाआरती 3 मई को

भोपाल ■ निसं

अग्रवाल समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान अग्रसेन महाराज एवं कुलदेवी माता लक्ष्मी की महाआरती महीने के प्रथम रविवार को निरंतर की जा रही है।

मुकेश गोयल ने बताया कि भगवान अग्रसेन के आदर्शों को आत्मसात कर एक-ईट एक-स्पये के सिद्धांत को अपनाकर समाज कल्याण की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। महाआरती में अग्रबंधु परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर जजमानी कर पुण्य लाभ भी अर्जित कर रहे हैं।

विनीत अग्रवाल एवं नितिन गुप्ता ने बताया कि भगवान अग्रसेन महाराज एवं कुलदेवी माता लक्ष्मी की महाआरती चैत्र नवरात्र 2024 से प्रारंभ की गई थी। आरती का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित एवं एकत्रित करना है। उन्होंने बताया कि निरंतर महाआरती होने से समाज में सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ श्रृद्धा-भक्ति भाव का संचार हो रहा है। भगवान अग्रसेन के आदर्शों को आत्मसात कर एक-ईट एक-रूपये के सिद्धांत को अपनाकर समाज कल्याण की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। रोहित गुप्ता ने बताया कि 26वीं महाआरती की रविवार, 5 अप्रैल 2026 सायं 6 बजे स्थान-श्री अग्रसेन वाटिका,आईटीसी पार्क, कमला पार्क के सामने भोपाल में आयोजित होगी। जिसकी जजमानी भेल अग्रवाल युवा मंडल द्वारा की जा रही है।

आयोजनकर्ताओं ने सभी अग्रबंधुओं से सपरिवार महाआरती में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह भी किया है।

परीक्षा हेतु बनाए गए हैं 06 परीक्षा केन्द्र

आज दो सत्रों में आयोजित होगी राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा

रायसेन ■ अमृत दर्शन

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 जिला मुख्यालय रायसेन पर ओएमआर आधारित विधि से आगामी आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 02.15 बजे से शाम 04.15 बजे तक दो सत्रों में 06 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।

आयोग द्वारा परीक्षा के संबंध में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परीक्षा केन्द्र प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्केनिंग, एचएचएमडी के माध्यम से तलाशी प्रारंभ की गई है। इन नवीन प्रक्रिया में समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी को परीक्षा के समय से 90 मिनिट पूर्व पहुचना होगा। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियो की त्रिस्तरीय जॉच की जाएगी। परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप अनुमत एवं वर्जित वस्तुओं की जानकारी चस्पा होगी, जिसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। परीक्षार्थियों की एचएचएमडी के माध्यम से दोनों सत्रों में जॉच (फ्रिस्किंग) की जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की जॉच महिला वीक्षक द्वारा (केबिन) में की जाएगी। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के पास विकल्प होगा कि वह अपनी फिस्किंग महिला अथवा पुरूष कर्मचारी से करवाना चाहते है। परीक्षार्थी स्वयं के साथ केवल बॉलपेन, एक पानी की पारदर्शी बॉटल, ई-प्रवेश पत्र व आईडी कार्ड साथ मे ला सकते है।

रायसेन में इन परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी परीक्षा: राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 जिला मुख्यालय रायसेन पर बनाए गए परीक्षा केन्द्र क्रमांक 31/1 शासकीय आदर्श कन्या उ.मा.विद्यालय सागर रोड रायसेन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष कमलेश नरवरे, इन केन्द्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन 26 अप्रैल तक

एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन

रायसेन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने गुरुवार को विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के लिए विद्यार्थी 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 26 अप्रैल तक हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। शेष नियम-निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों के सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियां: मुख्यमंत्री

रायसेन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विशेष रूप से महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में ठोस बदलाव लाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प को मूर्त रूप देते हुए मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं के हित में निर्णय लिये गये हैं। इन निर्णयों से 'नारी शक्ति वंदन' की भावना धरातल पर साकार हो रही है। राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा कर दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रदेश में लगभग 708.8 करोड़ रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। इससे महिलाओं को लगभग 344.5 करोड़ रुपये का सीधा लाभ हुआ है। यह वृद्धि केवल आय बढ़ाने का उपाय नहीं, बल्कि ग्रामीण और वनवासी महिलाओं को सम्मानजनक आर्थिक पहचान देने का प्रयास है। संग्राहकों को कुल 132.42 करोड़ रुपये का बोनस वितरित किया गया है। इसमें महिला संग्राहकों का हिस्सा लगभग 64.36 करोड़ रुपये है। तेंदूपत्ता संग्रहण जैसे पारंपरिक कार्य को आधुनिकता से जोड़कर सरकार ने यह सिद्ध किया है कि नारी शक्ति संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से समाज के हर स्तर पर परिवर्तन ला सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह पहल न केवल महिलाओं की आय बढ़ा रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सम्मान और सामाजिक स्थिति को भी नई ऊंचाई दे रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कुल 40.8 लाख संग्राहकों में लगभग 19.8 लाख महिलाएं हैं। इस तरह महिलाओं की भागीदारी लगभग 48.6 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि यह केवल वन आधारित आजीविका नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी एक बड़ा माध्यम है। 'नारी शक्ति वंदन' मध्यप्रदेश में एक जीवंत अभियान बन चुका है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की सहभागी हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार ने बहुआयामी योजनाएं लागू की हैं। इनमें 'चरण पादुका' योजना, सामाजिक सुरक्षा लाभ और वन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ ही ग्राम विकास एवं वन संरक्षण के लिए 35.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बिना हेलमेट पर जुर्माना की होगी कार्रवाई

आज से 15 दिन तक चलेगा हेलमेट अभियान

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 26 अप्रैल से हेलमेट अभियान की शुरुआत की जाएगी। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साईंकृष्णा एस. थोटा एवं एडिशनल एसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अभियान चलाया।

नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

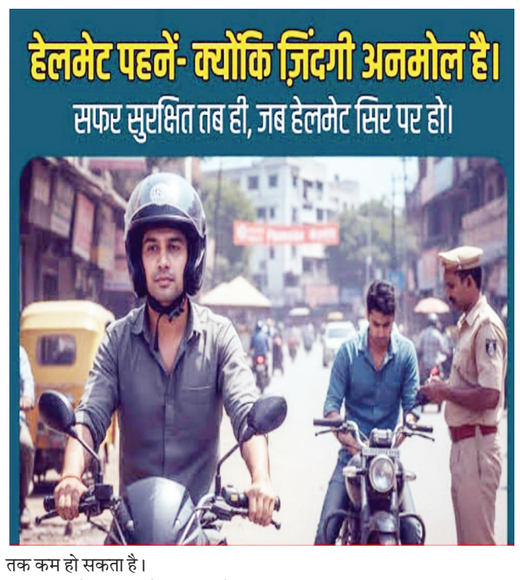

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों की संख्या दिनों दिन अधिक होती जा रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले चिंताजनक स्तर पर हैं। दुर्भाग्य से नर्मदापुरम जिले की इस मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सिर की चोट (Head Injury) मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होती है, और हेलमेट न पहनना इस जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है।दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सिर की चोट (हेड इंजरी) मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, हर वर्ष हजारों लोग केवल हेलमेट न पहनने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। कई वर्षों के आंकड़ों में यह पाया गया है कि दोपहिया वाहन की दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों में लगभग 80 प्रतिशत हेलमेट नहीं पहने हुए थे। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सही गुणवत्ता का हेलमेट पहनने से मृत्यु का खतरा लगभग 42% तक और गंभीर सिर की चोट का खतरा करीब 69% तक कम हो सकता है।

आज से 10 मई तक चलेगा अभियान: बिना हेलमेट चलने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी साथ ही बिना लाइसेंस चलने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी। लाइसेंस निलंबन की स्थिति में वाहन चलाने पर पुलिस की क्ब्हस्मशीन द्वारा बाद में चालानी कार्यवाही के समय लाइसेंस निलंबित बताएगा जिस पर पुलिस बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने की कार्यवाही कर सकेगी साथ ही यदि वाहन स्वामी चालक से अन्य हो तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकेगी।

हेलमेट पहनने के लाभ

दुर्घटना में गिरने या टक्कर लगने पर हेलमेट सिर को चोट से बचाता हैद्य मृत्यु की संभावना कम करता है शोध बताते हैं कि हेलमेट पहनने से सिर की घातक चोटों का खतरा काफी कम हो जाता है।

ब्रेन इंजरी से बचाव

मस्तिष्क पर सीधी चोट से कोमा, याददाश्त की समस्या हो सकती है, हेलमेट इससे सुरक्षा देता है।

कानूनी अनिवार्यता: भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

जन-जागरूकता पर भी जोर

अभियान के दौरान थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में नर्मदापुरम पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से 17 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला था। विगत वर्ष में प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान और नि:शुल्क हेलमेट वितरण किया गया था। हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सड़क दुर्घटना के समय सबसे अधिक खतरा सिर (Head) और मस्तिष्क (Brain) को होता है। सिर पर गंभीर चोट कई बार स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण बन जाती है। हेलमेट इस जोखिम को काफी हद तक कम करता है।

परिवार की सुरक्षा

आपकी सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। एक हेलमेट पूरे परिवार को दुख से बचा सकता है।

पुलिस की अपील

नर्मदापुरम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं और इस अभियान में सहयोग करें।

स्लॉट बुकिंग की सुविधा 30 से बढ़ाकर 9 मई तक

मध्यम एवं बड़े कृषकों को गेहूं विक्रय करने के लिये स्लॉट बुकिंग की सुविधा प्रारंभ

रायसेन ■ अमृत दर्शन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष युद्ध की विपरीत परिस्थिति के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 100 लाख मे.टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है।

इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम् संभागों के जिलों में 24 अप्रैल से शाम 6 बजे से मध्यम श्रेणी एवं बड़े किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह सुविधा पूर्व वर्ष अनुसार ही की गई है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर एवं चम्बल संभागों के जिलों में 25 अप्रैल (दोपहर 12 बजे) से मध्यम श्रेणी एवं बड़े किसानों से गेहूं उपार्जन के लिये स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 9 मई 2026 तक की गई है। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी के लिये प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन का कार्य जारी रहेगा। अभी तक प्रदेश मे समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये 7.76 लाख किसानों द्वारा 32.16 लाख मे.टन गेहूं के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किए जा चुके है।

प्रदेश में 3 लाख 96 हजार 97 किसानों से 16 लाख 57 हजार 526 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले 2,01,254 किसानों को 2166.29 करोड़ रुपये के भुगतान के लिये ईपीओ जनरेट किए गए। उपार्जन केन्द्र की क्षमता अनुसार उपज की तौल की जा सके एवं अधिक से अधिक किसानों से उपार्जन किया जा सके इसके लिये उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन प्रति उपार्जन केन्द्र पर गेहूं विक्रय के लिये स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन प्रति उपार्जन केन्द्र किया गया। कृषक द्वारा उपार्जन केन्द्र की प्रतिदिन तौल क्षमता 2250 क्विंटल के मान से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।

प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में किसान तथा मात्रा के स्लॉट बुकिंग कराकर गेहूं का उपार्जन किया जा सकेगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो एवं उपज विक्रय के लिए इंतजार न करना पड़े इसके लिये किसानों को जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाएं आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं।

किसानों को उपज की तौल समय पर हो सके इसके लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटो ग्राफ्स भारत सरकार के पीसी सेप पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है। किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई

इटारसी ■ अमृत दर्शन

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल इटारसी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरपीएफ भोपाल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. अभिषेक के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान ने स्टेशन पर हड़कंप मचा दिया है।

एक ही दिन में 70 गिरफ्तार, 66 हजार का जुर्माना: आरपीएफ इटारसी ने स्टेशन परिसर, आउटर और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न रेल अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 70 व्यक्तियों को रंगे हाथों दबोचा गया। इन सभी आरोपियों को भोपाल स्थित माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कुल 66,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया।

इटारसी जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर इतनी बड़ी संख्या में वेंडरों का पकड़ा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहां अवैध वेंडिंग का जाल काफी गहरा फैला हुआ है। आरपीएफ की इस निरंतर कार्रवाई ने अवैध वेंडिंग के गोरखधंधे की कमर तोड़ दी है।

आरपीएफ प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटरों और ट्रेनों में यात्रियों को परेशान करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरपीएफ की इस कार्रवाई की आम रेल यात्रियों ने भी सराहना की है, क्योंकि इससे ट्रेनों में भीड़ कम होगी और यात्रा अधिक सुरक्षित महसूस होगी।

कलेक्टर की अध्यक्षता में नर्मदा लोक कॉरिडोर की समीक्षा बैठक संपन्न

नर्मदा लोक कॉरिडोर शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी स्वीकार्य: कलेक्टर

नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

कलेक्टर ने रेवा सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान नर्मदालोक कॉरिडोर के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी के लिए विस्तृत वर्क शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएमओ नगर पालिका नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि वर्क शेड्यूल के कार्यों को साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित किया जाए तथा प्रत्येक सप्ताह कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि यथाशीघ्र पूरी टीम को मोबिलाइज कर कार्य में तेजी लाई जाए।

बैठक में कलेक्टर ने नर्मदालोक कॉरिडोर के सुचारू क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर मैनेजर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या भी बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदालोक कॉरिडोर शासन की एक महत्वाकांक्षी कार्यों में से एक है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तथा श्रमिकों को कार्य के दौरान उनका उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसी को समन्वय बनाकर समय अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू यादव, संयुक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम देवेंद्र प्रताप सिंह, सीएमओ नगरपालिका नर्मदापुरम श्रीमती हेमेश्वरी पटले उपस्थित रहे।

नपा अध्यक्ष पंकज चौरे ने जल संकट पर संभाला मोर्चा, ताकि शहर में जलापूर्ति हो सुनिश्चित

इटारसी ■ अमृत दर्शन

इटारसी शहर के वार्डों में गहराते जल संकट और सफाई व्यवस्था की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने शनिवार को मोर्चा संभाला। वार्ड 33 राठी कॉलोनी और वार्ड 03 हाउसिंग बोर्ड जैसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। राठी कॉलोनी में गिरते भू-जल स्तर के कारण फेल हो रहे बोरिंग पॉइंट्स का निरीक्षण कर उन्होंने तकनीकी टीम को निर्देश दिए कि नए वाल्व लगाकर पानी का प्रेशर मेंटेन किया जाए, ताकि अंतिम छोर तक जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके।

लीकेज और नई सप्लाई व्यवस्था: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शनि मंदिर के पीछे लंबे समय से पाइपलाइन लीकेज और कम प्रेशर की समस्या बनी हुई थी। नपा अध्यक्ष ने मौके पर ही निर्णय लिया कि इस क्षेत्र की लाइन को अब सीधे पानी की टंकी से जोड़ा जाएगा। इस बदलाव से लीकेज की समस्या खत्म होगी और पूरे क्षेत्र में पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंच सकेगा। निरीक्षण के दौरान जल प्रभारी संजय दुबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जिन्हें तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।

गंदगी फैलाने वाले पर होगा एक्शन: जल संकट के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को लेकर भी नपा अध्यक्ष सख्त नजर आए। हाउसिंग बोर्ड में खाली पड़े प्लॉटों पर जमा कचरे को देख उन्होंने नाराजगी जताई और स्वच्छता प्रभारी को संबंधित प्लॉट मालिकों को तत्काल लीगल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्लॉट मालिकों को बाउंड्रीवॉल बनानी होगी, ताकि खाली भूखंड डंपिंग यार्ड न बनें। इस दौरान पार्षद नारायण सिंह ठाकुर, एल्डरमैन अतुल शुक्ला, आशीष मालवीय और रमेश धूरिया सहित स्थानीय नागरिक मौजूद थे।

प्रेशर मैनेजमेंट: वार्ड 33 राठी कॉलोनी में नए वाल्व लगाकर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाएगा।

डायरेक्ट कनेक्शन: वार्ड 3 हाउसिंग बोर्ड की लाइन को सीधे पानी की टंकी से जोड़कर लीकेज की समस्या जड़ से खत्म होगी।

कानूनी कार्रवाई: खाली प्लॉटों पर गंदगी मिलने पर मालिकों को लीगल नोटिस और बाउंड्रीवॉल बनाने के निर्देश।

स्वच्छ सर्वेक्षण की गतिविधियां जारी

मनभावन पेंटिंग्स से सजाई जा रही नगर की दीवारें दिया जा रहा स्वच्छता का संदेश

नर्मदापुरम ■ अमृत दर्शन

नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 01 बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। नगरपालिका द्वारा गली मोहल्लों में जनजागरूकता अभियान, नाले नालियों की सफाई, घाटों की सफाई आदि अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही नगर की दीवारों पर मनभावन चित्रकारी की जा रही है।

प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कमलेश तिवारी ने बताया कि नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले और स्वच्छता शाखा प्रभारी दीक्षा तिवारी के मार्गदर्शन में स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

दीवारों को सजाया जा रहा है: स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश के 75 शहरों में नर्मदापुरम नगर को शामिल किया गया है। जिसके चलते स्वच्छता को सुनिश्चित करने के प्रतिदिन गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जिसमें नगर की समस्त खाली दीवारों पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी पेंटिंग्स बनवाई जा रही है। नगर की दीवारों पस्वच्छता के प्रति जनजागरूकता का संदेश देने वाले चित्र बनाए जा रहे हैं। जिससे शहर अब अलग लुक में दिखने लगा है।

तीन साल में सेप्टिक टेंक खाली कराना अनिवार्य: नपा के सतीश यादव ने बताया कि नगरपालिका द्वारा मलासुर अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण की गतिविधियों के तहत नगर में स्थित अपने घर या प्रतिष्ठान पर बने सेप्टिक टैंक को तीन वर्षों के अंदर खाली कराना अनिवार्य कर दिया गया।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी डी.पी.गोयल द्वारा प्रभा काम्पलेक्स के पास, मीनाक्षी चौक, आई.टी.आई. रोड, होशंगाबाद से प्रकाशित तथा श्री बालाजी प्रिन्टर्स, 21-एच, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल- 462023 (म.प्र.) से मुद्रित। संपादक- डी.पी.गोयल। मो.9827054436 भोपाल कार्यालय : 4240007. डाक पंजीयन - MP/HSD/04/2026-2028 व्यवस्थापक- डी.सी. पारे, मो. 8878623331 Email: amritdarshan@yahoo.com (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।)।